कोलकाता शनिवार 3 सितंबर, 2022, रु. 6.00 (10 पेज) कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित (डाक रविवार, 4 सितंबर, 2022 पेज 10 रु. 6.00)

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

प्रधानमंत्री ने कहा

सीने से उतर गया गुलामी का बोझ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोच्चि में भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत 'आइएनएस विक्रांत' का जलावतरण किया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसे बड़े युद्धपोतों के निर्माण की घरेलू क्षमताएं हैं। मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना के नए निशान (ध्वज) का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि आज देश ने भारत ने गुलामी के एक निशान, 'गुलामी के एक बोझ' को सीने से उतार दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ' विक्रांत विराट है, विहंगम है, विशाल है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है। यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में स्वदेश निर्मित जहाज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। इस जहाज का नाम नौसेना के एक पूर्व जहाज 'विक्रांत' के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने विमानवाहक पोत की कुछ विशेषताओं के बारे में भी बात की। उन्होंने इसे 'फ्लोटिंग एअरफील्ड, एक तैरता हुआ शहर' के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि आइएनएस विक्रांत में जितनी बिजली पैदा होती है उससे पांच हजार घरों को रोशन किया जा सकता है।

इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह आइएनएस विक्रांत को मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा, 'आज दो सितंबर, 2022 की ऐतिहासिक तारीख को, इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने, गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है।' उन्होंने कहा, 'भारतीय नौसेना के झंडे पर अब तक गुलामी की पहचान बनी हुई थी। लेकिन आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होकर नौसेना का नया ध्वज समुद्र और आसमान में लहराएगा।' नौसेना ने पहले कहा बाकी पेज 8 पर

विशाल, विराट, विहंगम

विक्रांत

कोच्चि में शुक्रवार को विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत को नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

-संबंधित खबर पेज 8

थरूर ने निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर उनसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के आगामी चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची प्रकाशित करने की मांग की है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ऐसी खबर है कि असम के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने भी मिस्त्री को पत्र लिखकर निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की है।

कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव

उन्होंने ऐसे समय में पत्र लिखे हैं जब निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ बाकी पेज 8 पर

बेबाक बोल

भाग दरबारी

आज जब कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव का एलान हो गया है तो देखना होगा कि चिट्ठी-क्रांति करने वाला समूह चुनाव में भाग लेता है या चुनावी प्रक्रिया खट्टी है कह कर मुंह फेर लेता है। पेज 7

छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती ट्रेन से फेंका, मौत

चंडीगढ़, 2 सितंबर (एजंसी)।

हरियाणा के फतेहाबाद में टोहाना स्टेशन के पास छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक व्यक्ति ने 32 वर्षीय महिला को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। इस कारण कथित तौर पर महिला की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना महिला के नौ साल के बेटे की मौजूदगी में हुई। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने कहा कि महिला टोहाना जाने के लिए रोहतक के लखन माजरा के पास से यात्री ट्रेन में सवार हुई थी। जीआरपी के एक अधिकारी ने बताया कि घटना गुरुवार रात की है। जीआरपी थाना, हिसार के एसएचओ नरेश कुमार ने

दिल्ली से टोहाना जा रही ट्रेन में हुई वारदात *महिला* के नौ वर्षीय पुत्र की मौजूदगी में हुई घटना।

कहा कि महिला अपने बेटे के साथ यात्रा कर रही थी। उन्होंने कहा, 'यात्री ट्रेन दिल्ली से टोहाना जा रही थी और महिला और उसका बेटा लखन माजरा से उसमें सवार हुए थे।' कुमार ने कहा कि अधिकांश यात्री पिछले स्टेशन पर ट्रेन से उतर चुके थे और घटना के दौरान ज्यादातर डिब्बे खाली थे।

उन्होंने कहा कि टोहाना स्टेशन पर महिला का पति उनका इंतजार कर रहा था। अधिकारी बाकी पेज 8 पर

तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी। तीस्ता 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 26 जून से गुजरात पुलिस की हिरासत में हैं।

प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ बाकी पेज 8 पर

अहमदाबाद में मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी के दौरान तीस्ता सीतलवाड़।

न्यायाधीशों ने कहा, तीस्ता एक महिला हैं। वे दो महीनों से हिरासत में हैं और जांच तंत्र को सात दिनों की अवधि के लिए हिरासत में पूछताछ का लाभ भी मिला है।

उनके खिलाफ कथित अपराध 2002 से संबंधित हैं और अधिक से अधिक 2012 तक संबंधित दस्तावेज पेश करने की मांग की गई थी।

तीस्ता 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 26 जून से गुजरात पुलिस की हिरासत में थीं।

ट्विटर ने जानबूझकर देश के कानून की अवज्ञा की : केंद्र

बंगलुरु, 2 सितंबर (एजंसी)।

केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि ट्विटर ने जानबूझकर भारत के कानूनों का पालन नहीं किया और उसकी अवज्ञा की तथा देश की सुरक्षा में इस सोशल मीडिया मंच की कोई भूमिका नहीं है। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआइटीवाई) ने गुरुवार को ट्वीट हटाने और अकाउंट ब्लाक करने से जुड़े सरकारी आदेशों के खिलाफ ट्विटर की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियों के संबंध में पेश 101 पन्नों के बयान में यह दलील दी।

-पूरी खबर पेज 8

सागर व भोपाल में चार चौकीदारों की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार

भोपाल, 2 सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य के सागर एवं भोपाल शहरों में पिछले पांच दिन में चार चौकीदारों की हत्या करने के मामले में शुक्रवार को एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान शिव प्रसाद धुर्वे (18) के रूप में उसके आधार कार्ड से हुई है। उन्होंने बताया कि उसने सागर शहर में तीन चौकीदारों और भोपाल में एक चौकीदार की हत्या की है।

उन्होंने बताया कि घटना के वक्त ये चारों चौकीदार ड्यूटी पर थे और सो रहे थे। पुलिस ने बताया कि उसने शुक्रवार को गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले भोपाल में चौकीदार की हत्या कर दी थी। सागर के पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने कहा कि 18 साल और आठ महीने के धुर्वे ने चार हत्याओं को कबूल करते हुए कहा कि वह सोशल मीडिया से प्रभावित था और प्रसिद्ध होने के लिए उसने इन घटनाओं को अंजाम दिया। धुर्वे की मानसिक स्थिति के बारे में पूछे जाने पर नायक ने कहा कि वह सामान्य प्रतीत होता है। नायक ने कहा कि यह 'साइको किलर' मामला नहीं है। इससे पहले राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि चार चौकीदारों की हत्या के आरोपी धुर्वे को सागर पुलिस ने भोपाल में शुक्रवार तड़के मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया।

नया निशान

औपनिवेशिक पहचान वाली लाल धारियां हटाई गईं

भारतीय नौसेना को मिला नया ध्वज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भारतीय नौसेना को शुक्रवार को नया ध्वज मिला। नए ध्वज में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाल धारियों को हटा दिया गया है जिसे 'क्रास आफ सेंट जार्ज' कहा जाता है। यह औपनिवेशिक युग की याद दिलाता था। नए ध्वज में अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। नौसेना के मूल मंत्र को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोच्चि में नया ध्वज और चिह्न, राष्ट्र को समर्पित किया।

ब्रिटिश शासन से लेकर गणराज्य के प्रतीक तक यह झंडा सदियों में विकसित हुआ है। यह

नए ध्वज में प्रतीक शिवाजी महाराज की मुहर पर आधारित।

ध्वज अनिवार्य रूप से एक विशेष डिजाइन वाला झंडा होता है, जो जहाजों या नौसैन्य बल की पहचान और राष्ट्रीयता को दर्शाता है, खासकर गहरे समुद्र में। ध्वज के 'फ्लाई' क्षेत्र में जुड़वां सुनहरी सीमाओं के साथ एक अष्टकोणीय आकार शामिल किया गया है, जो शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित है। नौसेना द्वारा जारी एक वीडियो के अनुसार, नीले अष्टकोणीय आकार में एक लंगर के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक को शामिल किया गया है जो दृढ़ता को दर्शाता है। यह नौसेना के आदर्श वाक्य 'शं नो वरुणः' के साथ एक ढाल पर लगाया गया है, जिसका अर्थ है: 'हमारे लिए शुभ हो ओह वरुण'। अष्टकोणीय आकार आठ दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय नौसेना की बहु-दिशात्मक पहुंच और बहु-दिशात्मक बाकी पेज 8 पर

नाचने से मना करने पर युवक की छत से फेंक कर हत्या

जांजगीर, 2 सितंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में बिन बुलाए मेहमानों ने जन्मदिन की पार्टी के दौरान युवक की छत से नीचे फेंककर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में आठ बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के चांपा थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण तुलसी धर्मशाला में बुधवार-गुरुवार की रात में कमलेश्वर देवांगन की हत्या के आरोप में पुलिस ने आठ बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि धर्मशाला में कमलेश्वर देवांगन अपने दोस्त बिन्नी देवांगन के जन्मदिन समारोह में शामिल होने गया था। समारोह में कुछ महिलाएं भी थीं। जब सभी वहां नृत्य कर रहे थे तब दो आरोपी किरण सारथी और मनीष सारथी कार्यक्रम स्थल में जबरन घुस गए और साथ में नाचने लगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब कमलेश्वर और कुछ अन्य लोगों ने दो आरोपियों को वहां से जाने के लिए कहा तब दोनों उनसे झगड़ने लगे। बाद में आरोपियों ने अपने छह अन्य साथियों को कार्यक्रम स्थल पर बुला लिया और सभी कमलेश्वर और उसके दोस्तों की पिटाई करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब कमलेश्वर उनसे बचने के लिए छत की ओर भागा तब आरोपियों ने उसका पीछा किया और बाद में उन्होंने कमलेश्वर को दो मंजिला इमारत की छत से नीचे फेंक दिया। इस घटना में कमलेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद कमलेश्वर के मित्र उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से उसे बिलासपुर के अपोलो अस्पताल भेजा गया।अस्पताल में इलाज के दौरान कमलेश्वर की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कमलेश्वर के मित्रों की शिकायत पर पुलिस ने मनीष, किरण और छह अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

अस्पताल के शौचालय में महिला का लटकता हुआ शव मिला

कोलकाता, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

दक्षिण कोलकाता के एक अस्पताल के शौचालय से एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव फंदे से लटक रहा था। बताया जाता है कि लंबे समय से उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। हरिदेवपुर थाना पुलिस के मुताबिक, महिला का नाम नीलिमा साहा है, वह मुर्शिदाबाद जिले की रहने वाली है। पिछले महीने 17 अगस्त को दक्षिण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। गुरुवार की रात भी उनकी केमो थेरोपी की गई थी, लेकिन शुक्रवार सुबह शौचालय से उनका शव फंदे से लटकता हुआ देखा गया। पुलिस के मुताबिक, अस्पताल के नियमानुसार कोई भी कैंसर पीड़ित मरीज अगर शौचालय में जाता है तो भीतर से दरवाजा बंद नहीं कर सकता।

आज सुबह एक महिला ने शौचालय के दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई। जब वह दरवाजा खोल कर भीतर घुसी तो देखा कि महिलाका शव छत से लटक रहा है। पुलिस ने शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक तौर पर इसे आत्महत्या का मामला ही माना जा रहा है। हालांकि महिला की आर्थिक स्थिति अच्छी ही थी। परिवार के साथ भी नियमित तौर पर संपर्क रहता था। पुलिस के मुताबिक, कैंसरपीड़ित महिला को लग रहा था कि शायद वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी। ऐसी हालत में इलाज के कारण मानसिक अवसाद में आत्महत्या का रास्ता चुना। महिला के परिवार को इस बारे में सूचित किया गया है। पुलिस अस्पताल प्रबंधन से भी इस बारे में बातचीत कर रही है।

बिहार में महिला ने अपनी तीन बेटियों की हत्या की, गिरफ्तार

बक्सर, 2 सितंबर (भाषा)।

बिहार के बक्सर जिले में अपनी तीन बच्चियों की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में शुक्रवार को एक महिला को गिरफ्तार किया गया। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी पिंकी देवी ने अपनी बच्चियों-पूनम (8), रोनी (7) और बबली (4) की हत्या क्यों की। पिंकी ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के बरकी गाई घाट गांव की रहने वाली है। पिंकी के पड़ोसियों ने शुक्रवार सुबह बच्चियों के शव देखे और फिर पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। सहायक पुलिस अधीक्षक (डुमरांव) राज ने संवाददाताओं से कहा कि पिंकी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

खबर कोना

ओड़ीशा में कोरोना के 226 नए मामले, एक की मौत

भुवनेश्वर, 2 सितंबर (भाषा)।

ओड़ीशा में शुक्रवार को कोरोना विषाणु संक्रमण के 226 नए मामले सामने आने के बाद कोविड महामारी के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 13,28,070 तक पहुंच गई। एक स्वास्थ्य बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। बुलेटिन के मुताबिक, इसी अवधि में भुवनेश्वर में कोविड-19 के 81 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। ओड़ीशा में इस घातक विषाणु के कारण अब तक 9,178 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में फिलहाल 1,797 मरीज उपचाराधीन हैं जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 228 लोगों को संक्रमणमुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। बुलेटिन के मुताबिक, ओड़ीशा में अब तक 13,17,042 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं।

झारखंड : सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए

सरायकेला, 2 सितंबर (भाषा)।

झारखंड के सरायकेला-खरसावां में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कोबरा, झारखंड जगुआर और राज्य पुलिस के एक संयुक्त अभियान के दौरान ये माओवादी मारे गए।कोल्हान संभाग के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय लिंडा ने एजंसी से कहा कि कुचाई थाना क्षेत्र के बरुदा जंगल में एक अभियान के दौरान भाकपा (माओवादी) के दो सदस्य मारे गए। उन्होंने कहा कि दोनों की पहचान 32 वर्षीय काली मुनाद और रीला माला मांझी (22) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल ने शवों को बरामद कर लिया है और उनके पास से हथियार तथा गोला-बारूद भी मिला है।

हिमंत बिस्व सरमा ने पूर्वी कमान के वायु सेना प्रमुख से राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की

गुवाहाटी, 2 सितंबर (भाषा)।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को वायु सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख एअर मार्शल डीके पटनायक के साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। एअर मार्शल पटनायक ने यहां शर्मा के कार्यालय पर उनसे मुलाकात की। सरमा ने ट्वीट किया कि पूर्वी वायु सेना कमान के प्रमुख एअर मार्शल डीके पटनायक से मुलाकात की। विशेष रूप से पूर्व और पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा की। निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करने के लिए असम के लोगों की ओर से वायु सेना के प्रति आभार प्रकट किया।

'आयल इंडिया परियोजना के लिए मुआवजा दिए बिना अरुणाचल में आदिवासियों को जबरन नहीं हटाया जाएगा'

गुवाहाटी, 2 सितंबर (भाषा)।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सूचित किया है कि आयल इंडिया लिमिटेड परियोजना के लिए अरुणाचल प्रदेश के दो गांवों में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिए बिना आदिवासियों को जबरन नहीं हटाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रालय के आश्वासन के बाद, मानवाधिकार आयोग ने चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन आफ इंडिया (सीडीएफआइ) द्वारा दायर शिकायत को बंद कर दिया है। सीडीएफआइ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने एनएचआरसी को यह भी सूचित किया है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आयोग ने 31 अगस्त को एक आदेश में शिकायत को बंद कर दिया। इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए, सीडीएफआइ के संस्थापक सुहास चकमा ने कहा कि आयोग का यह सुरक्षात्मक आदेश परियोजना से प्रभावित चकमा और देवरी लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुडोक्का नाला और सोमपोई-द्वितीय गांवों से चकमा और देवरी लोगों को कथित तौर पर जबरन हटाए जाने के खिलाफ एक शिकायत 20 जनवरी को दायर की गई थी।

असम में मदरसों को ध्वस्त करना अवैध : विपक्ष

गुवाहाटी, 2 सितंबर (भाषा)।

असम में कथित 'जिहादी गतिविधियों' से जुड़े मदरसों को ध्वस्त करने के राज्य सरकार के अभियान की विपक्ष ने कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'पूरी तरह अवैध' करार दिया और कहा कि 'एक विशेष समुदाय' को लक्षित किया गया है। भाजपा सरकार ने पिछले एक महीने के भीतर राज्य के विभिन्न हिस्सों में तीन मदरसों को उनके शिक्षकों को गिरफ्तार करने के बाद ध्वस्त कर दिया गया। शिक्षकों को कथित तौर पर 'जिहादी' गतिविधियों में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया था।

हालांकि, प्रत्येक अवसर पर ढांचा गिराने का आधिकारिक कारण जिहादी गतिविधियों के साथ किसी भी तरह का संबंध होने के बजाय दोषपूर्ण निर्माण या भूमि मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित था। सत्ता पक्ष के केवल राजनीतिक नेता ही मीडिया में आम तौर पर बयान देते हैं कि मदरसों को उनके परिसरों से कथित तौर पर जिहादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ध्वस्त किया गया है।

प्रशासन ने चार अगस्त को मोरीगांव जिले के मोइराबारी में, 29 अगस्त को बारपेटा के ढकलियापारा में और 31 अगस्त को बोंगईगांव के जोगीघोपा में मदरसों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आल असम तंजीम मदारिस कौमिया के सचिव अब्दुल कादिर ने बातचीत में कहा कि मोइराबारी मदरसे को एक नोटिस भेजे जाने के बाद ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि इमारत छोटी थी और बिजली का कनेक्शन अवैध था।

बचाव पटना में शुक्रवार को लगातार मानसूनी बारिश के बाद नाव से गंगा के पार सब्जियां ढोकर ले जाते किसान।

आइआइटी गुवाहाटी में आधुनिक कैंसर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा

गुवाहाटी, 2 सितंबर (भाषा)।

कैंसर सहित अन्य गैर-संक्रामक बीमारियों के क्षेत्र में अनुसंधान और उनकी जांच के लिए किफायती किट विकसित करने के लक्ष्य से सरकार गुवाहाटी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) में अनुसंधान केंद्र की स्थापना करेगी। शुक्रवार को यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, आइआइटी ने इस संबंध में कारकिनोस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आइआइटी-गुवाहाटी के 29वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, संस्थान के परिसर में 'सेंटर फार एडवांस रिसर्च आन डायग्नोस्टिक इन कैंसर' (सी-कार्ड) स्थापित किया जाएगा। इसमें उपकरणों का इंतजाम करने और इसके संचालन की जिम्मेदारी केएचपीएल की होगी। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर आइआइटी-गुवाहाटी के निदेशक प्रोफसर टीजी सीताराम और कारकिनोस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ आर वेंकटरमण ने हस्ताक्षर किए।

असम उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध : सरमा

गुवाहाटी, 2 सितंबर (भाषा)।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वसरमा ने दिल्ली के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल को ट्विटर पर निशाना बनाना जारी रखते हुए शुक्रवार को दावा किया कि उनका राज्य, दिल्ली की तुलना में कुछ पहलुओं में छोटा होने के बावजूद 'उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध' है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अस्पताल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में लगी हुई है। भाजपा के नेता सरमा ने केजरीवाल को टैग करते हुए ट्वीट किया कि उत्कृष्टता के लिए हमारी प्रतिबद्धता सर्वोच्च है। हम काम करके दिखाते हैं और डींग नहीं हांकते। दिल्ली की तुलना में कुछ पहलुओं में छोटा राज्य होने के बावजूद, असम में 21 अत्याधुनिक मेडिकल कालेज/अस्पतालों का निर्माण किया रहा है। छह का काम पूरा हो गया, तीन का काम इस वर्ष पूरा किया जाना है। जबकि शेष का काम पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। केजरीवाल और शर्मा के बीच पिछले कुछ दिन से ट्विटर पर जुबानी जंग जारी है।

यह विवाद तब शुरू हुआ था, जब केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि स्कूल बंद करना कोई समाधान नहीं है। उन्होंने खराब परिणामों के कारण असम में कुछ स्कूलों को बंद किए जाने का दावा करने संबंधी एक खबर भी साझा की थी।

असम के मुख्यमंत्री ने आइएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने की सराहना की

गुवाहाटी, 2 सितंबर (भाषा)।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वसरमा ने शुक्रवार को कहा कि स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आइएनएस 'विक्रांत' को नौसेना के बेड़े में शामिल करना प्राचीन भारत के शासकों की समृद्ध नौसैनिक शक्ति को एक उचित सम्मान है। सरमा ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आइएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करना अहोम, मराठा और चोल शासकों की समृद्ध नौसैनिक विरासत को उचित सम्मान है।

भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत का शुक्रवार को जलावतरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में एक समारोह के दौरान स्वदेश में निर्मित पोत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया।

-: Tender Notice :-

West Bengal Police Housing & Infrastructure Development Corpn Ltd having its office at 3rd floor, Araksha Bhawan, Block- DJ, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-91 is inviting open tender from experienced agency for works of WBPHIDCL/EE-(HQ-I)/NIT-128(e)/2022-2023 (6th call), Emergent and Routine maintenance Works of Civil (All Buildings, S&P) for different buildings of Sadar Sub-Division (Anandapur P.S, Garbeta P.S, Keshpur P.S, Goaltore P.S, Salboni P.S, Kotwali P.S, All Woman P.S in Midnapore, Gurguripal P.S and All Out-post in Sadar Sub-Division) in the district of Paschim Medinipur from 01.10.2022 to 31.03.2023. **Estimated Amount put to Tender Rs. 23,35,928/-, Tender Id: 2022_WBSPH_401040_1, Last date & time of submission of bids online is 19.09.2022 at 16.00 PM. For further details please visit www.wbtenders.gov.in**

Hooghly Zilla R.M.C. invites e-Tender vide N.I.T. No. 19/HZRMC/2022-2023 Dated 02.09.2022. Last date of submission of Bid- 20.09.2022 up to 1 P.M. The details of the e-Tenders are available on the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
**Secretary,
Hooghly Zilla R.M.C.**

Malegaon Municipal Corporation, Malegaon
Dist. Nashik, Maharashtra State
Re E-Tender Notice No. Ws/Jal-Mal/02/2022-23

The Commissioner Malegaon Municipal Corporation invites Online Tender in B-1 Format for the work of SEWERAGE SCHEME FOR MALEGAON CITY UNDER AMRUT ABHIYAN, Tal. MALEGAON, Dist. Nashik, In the State of Maharashtra, Cost of Tender Rs. 5,47,59,932/- & for all relevant information that is scope of work, time table will be made available on web site https://www.mahatenders.gov.in/ form 03/09/2022 for detailed information.

Date : 03/09/2022 to 19/09/2022

Commissioner
Malegaon Municipal Corporation, Malegaon

"आईये उन सभी लोगों को याद करे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुती दि."

पंजाब नैशनल बैंक | punjab national bank

पंजाब नैशनल बैंक
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
प्रधान कार्यालय: मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
पहली मंजिल, सी-13, सेक्टर - 1, नोएडा - 201301 (उ.प्र.)

95 GSM MICR पेपर के 2,50,000 KGs की खरीद के लिए ई-निविदा

[illegible]

बैंक के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 19.09.2022 अपराह्न 01:00 बजे तक है।

(मुख्य प्रबंधक)

पश्चिम मध्य रेल
संकेत एवं दूरसंचार विभाग
खुली निविदा
निविदा दिनांक/30/08/2022

उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता/निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु निर्धारित ई निविदा आमंत्रित करता है। **ई निविदा सूचना क्रमांक**- जबल/एस. एंड टी/निर्माण/निविदा/126/टेली दिनांक 30.08.2022, **कार्य का नाम लोकेशन सहित**- सतना - पन्ना सेक्शन (7 स्टेशन, 76 किलोमीटर) की नई ब्रॉड गेज लाइन के प्रावधान के संबंध मं टेंचिंग, केबल लेइंग, ज्वाइंटिंग, स्पलाइसिंग और ईसी सॉकेट लगाने आदि सहित इनडोर और आउटडोर दूरसंचार उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य एवं सतना- रीवा सेक्शन का शेष कार्य पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में करना है। **निविदा का अनुमानित मूल्य**- रू. **11,60,14,162.02, कार्यालय का पता**- उप मुख्य संकेत एंव दूरसंचार अभियंता/निर्माण/जबलपुर (प्रथम तल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भवन,जबलपुर), **बयाना राशि**- रू. 7,30,100/-, **समापन अवधि**- 18 माह, **निविदा बंद होने की तिथि एवं समय (15:00 बजे तक)**- समय 15:00 बजे 07.10.2022, उपरोक्त निविदा सूचना की पूर्ण जानकारी रेलवे वेबसाईट https://www.ireps.gov.in उपलब्ध है तथा उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता/निर्माण कार्यालय जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है। उपरोक्त निविदा उक्त वेबसाईट से केवल ऑनलाईन आवेदन ही की जा सकती है।

**उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता/निर्माण
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर**

कोरोना को है हराना,
तो टीकाकरण जरूर कराना

TENDER NOTICE

WBCADC is inviting e-tenders for (i) Supply, Installation, Testing & Commissioning of 2 HP Paddle wheel Areators [15 (Fifteen) to 20 (Twenty) nos.] for different Projects of WBCADC, (NIT no.-24/2022-23) & (ii) Supply, Installation, Testing and Commissioning of Solar System [15 (Fifteen) to 20 (Twenty) nos.] towards Run the 2 HP Motors of Areators of different Projects of WBCADC, (NIT no.-25/2022-23). The intending tenderers will have to collect the tender documents within **19.09.2022 up to 18.30 hours** by downloading through the website stated below. For details visit the website **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-
Administrative Secretary
WBCADC**

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

Notice Inviting e-Tender No. : UKM/007(e)/2022-23 (2nd Call) Date- 02/09/2022
1.Supply, Installation, Testing and Commissioning of Fire Fighting, Fire Sprinkler system at Mahamaya Sisu-O-Matrimangal Kendra Under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date – 19/09/2022 up to 05:00 pm. For Details:- wbtenders.gov.in

**Sd/-
Chairman,
U.K. Municipality**

CANNING-II PANCHAYAT SAMITI
Jibantala, South 24 Pgs.
To whom it may concern

Abridged Tender Notice (e-NIT No. 09 of 2022-2023 date 31.08.2022) for Supply & installation of 9 Mtr Minimast light 08 places under Canning-II Panchayat Samiti, Jibantala, South 24-Parganas (detail information will be available www.etender.wb.nic.in & office Notice Board or Engineering Section of this office).

**Sd/-
Executive Officer
Canning-II Panchayat Samiti**

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय: एसीई (डीआर) परि.-III, द्वारा कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-VIII
यमुना विहार सीवेज शोधन संयंत्र (डा. अम्बेदकर कॉलेज के समीप), दिल्ली-110094
फोन: 011-22813593, ईमेल: eecdr8@gmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रैस एनआईटी सं. 08(2022-23), ईई(सी)डीआर-VIII

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित अनुबंध मूल्य (ईसीबी)/ निविदा राशि (रु.)	धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.)	निविदा प्रॉसेसिंग शुल्क (रु.)	निविदा जारी की तिथि/ निविदा आईडी	ई-प्राप्ण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	मंडोली जेल दिल्ली के निकट वजीराबाद रोड से लगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पम्प के समीप हर्ष विहार में 3.85 एमजीडी डब्ल्यू पीएस के चारो ओर बाउण्ड्री वाल का निर्माण।	5424214/-	108500/-	1000/-	2022_DJB_ 228669-1 तिथि 2.9.2022	23.9.2022 के 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — हस्ता./- (आर.के.जैन)
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 318 (2022-23) — कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-VIII

"कोरोना रोकें; मास्क पहनें; शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें"

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय: कार्य. अभि. (ई एंड एम) एचपी-II
हैदरपुर वाटर वर्क्स, दिल्ली-110085
टेली. नं. 011-27552446-47, ईमेल आईडी: eeemhp2.djb@nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संक्षिप्त प्रैस एनआईटी सं.-03(2022-23)/ईई (ईएंडएम) एचपी-II

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि (रु.)	ई-प्राप्ण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्राप्ण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	हैदरपुर वाटर वर्क्स फेज-II में रोबोटिक मशीन तकनीक द्वारा जलाशय नं. 1 की सफाई।	मद दर	रु. 63550/-	निविदा आईडी: 2022_DJB_228629-1 प्रकाशन तिथि 1 सित. 2022 17.00 बजे से	15 सित. 2022 के 2.30 अप. तक

इस संदर्भ में सभी नियमों एवं शर्तों सहित एनआईटी के अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — हस्ता./- (आर.पी. मीना)
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 316 (2022-23) — कार्यपालक अभियंता (ईएंडएम) एचपी-II

"कोरोना रोकें; मास्क पहनें; शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें"

TENDER NOTICE

WBCADC is inviting e-tenders for Establishment of Semi-Automated Feed Mill Plant under RKVY Fund under WBCADC Debra Project (NIT no. 26/2022-23, **Estimated Value :** Rs. 18,15,653.00). The intending tenderers will have to collect the tender documents within **19.09.2022 up to 18.30 hours** by downloading through the website stated below. For details visit the website **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-
Administrative Secretary
WBCADC**

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

जनसत्ता क्लासीफाइड

CHANGE OF NAME

I hitherto known as CAESI (DAS) MUKHERJEE alias CAESI MUKHERJEE DAS w/o SUBRATA MUKHERJEE res. of F1/19-1, NORTHLAND ESTATE, TYPE-IV, MSF FACTORY QUARTER PREMISES, PO. NAWABGANJ, PS.- NOAPARA, ICHAPORE, WEST BENGAL - 743144 have changed my name and shall hereafter be known as CAESI MUKHERJEE. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

खबर कोना

मुसलिम डिलीवरी बाय मामले पर भड़कीं महुआ मोइत्रा

कोलकाता, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

हैदराबाद के एक शख्स के फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी की ओर से मुस्लिम डिलीवरी बाय न भेजने के निर्देश पर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। महुआ मोइत्रा ने कंपनी से ऐसे ग्राहकों का नाम सार्वजनिक करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी को ऐसे ग्राहकों को काली सूची में डालकर पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के शख्स की यह हरकत पूरी तरह से अवैध है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया– घृणा और कट्टरता के नार्मलाइजेशन को देखकर दुख हो रहा है। जो छिपा हुआ व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हुआ करता था, वह अब बहुसंख्यकवाद की सार्वजनिक उद्घोषणा बन रहा है।' महुआ ने आगे लिखा– स्विगी प्लीज आप ग्राहक को काली सूची में डालिए और उसका नाम सार्वजनिक कीजिए। इतना ही नहीं, पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराइए। यह पूरी तरह से अवैध है।

मंत्री श्रीकांत महतो की सुरक्षा घटाई गई

कोलकाता, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

क्रेता सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री व शालबनी के विधायक श्रीकांत महतो की सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक, उन्हें पहले वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलती थी, अब उन्हें एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। मालूम हो कि तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी बैठक में दल विरोधी बातें करने, दल के कई नेताओं के खिलाफ बोलने, जिसमें दल के उच्च स्तर के नेता भी शामिल हैं की वजह से हाल में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अब सुरक्षा व्यवस्था में कमी करके दूसरे विधायकों की तरह उन्हें भी एक्स श्रेणी में शामिल कर दिया गया है।

दुर्गापूजा : मिलावटी भोजन के खिलाफ निगम चलाएगा अभियान

कोलकाता, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

दुर्गापूजा के दौरान कोलकाता नगर निगम की ओर से मिलावटी भोजन के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का फैसला किया गया है। मालूम हो कि दुर्गा पूजा की शुरुआत होने में ज्यादा देर नहीं है। पूजा पंडालों को आखिरी रूप देने का कार्य तेजी से चल रहा है। दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल परिक्रमा के साथ ही होटल, रेस्तरां से शुरू कर सड़क किनारे लगे फूड स्टालों में लोगों की भीड़ लगी रहती है। दुर्गा पूजा के दौरान फूड स्टालों में बेचा जा रहा खाना कितना सुरक्षित है, इसकी जांच के लिए कोलकाता नगर निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी फूड स्टालों में तैयार किए जा रहे खानों की जांच करेंगे। इसके साथ ही खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का भी नमूना एकत्रित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से समय समय पर इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं।

ईडी दफ्तर पहुंचे अभिषेक, सात घंटे तक की गई पूछताछ

कोलकाता, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

कथित कोयला चोरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुक्रवार को सात घंटे तक पूछताछ किए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो वह उन्हें सलाखों के पीछे डाल दें।

बनर्जी ने कहा कि वह धमकियों और केंद्रीय एजंसी द्वारा समन जारी किए जाने से नहीं डरेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी, तो मैं 30 बार पूछताछ का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं भाजपा के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। मैंने

संवाददाताओं को संबोधित करते अभिषेक बनर्जी।

राष्ट्रध्वज के मामले पर उनके (शाह के) बेटे पर निशाना साधा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे डराने के लिए ईडी और सीबीआइ (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) का इस्तेमाल किया जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआइ) के सचिव जय शाह एक वीडियो क्लिप में भारत द्वारा पाकिस्तान को एक रोमांचक क्रिकेट मैच में हराने के बाद राष्ट्रीय ध्वज लहराने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए प्रतीत हुए। दुबई में एशिया कप मुकाबले के 28 अगस्त को हुए इस मैच की क्लिप ने विवाद खड़ा कर दिया।

उन्होंने कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वह साबित करें कि मैंने कुछ गलत किया है और मुझे सलाखों के पीछे डाल दें। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया कि देश के गृह मंत्री का केवल एक ही काम है – 'विपक्षी दलों की निर्वाचित राज्य सरकारों को गिराने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त करना।'

'केंद्र की भाजपा सरकार ने पवित्र संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है'

कोलकाता, 2 सितंबर (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद अभिषेक बनर्जी से कोयला चोरी घोटाले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को पूछताछ किए जाने के बीच उनकी पार्टी ने केंद्रीय एजंसी का कथित राजनीतिकरण करने और उन्हें कठपुतलियां बनाने को लेकर भाजपा की आलोचना की।

भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया। नाराज तृणमूल कांग्रेस ने विभिन्न केंद्रीय जांच एजंसी को 'भाजपा की कठपुतलियां' करार दिया और कहा कि यह शर्म की बात है कि केंद्र में भाजपा की सरकार ने देश की 'पवित्र संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है।' उसने कहा कि ये एजंसी बदले की राजनीति के भाजपा के एजंडे के तहत सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अभिषेक बनर्जी कोयला चोरी घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से साल्ट लेक में सीजीओ काम्प्लेक्स स्थित एजेंसी के कार्यालय में पूछताछ की गई।

तृणमूल ने ट्वीट किया कि केंद्रीय एजंसी भाजपा की कठपुतली बनकर रह गई हैं। भाजपा को जब भी खतरा महसूस होता है, वह इन 'तोतों' को उन लोगों के पीछे छोड़ देती है, जिन्होंने अपनी वफादारी का सौदा नहीं किया है। तृणमूल ने ट्विटर पर भाजपा नेताओं के उस समय के कुछ वीडियो साझा किए, जब भाजपा केंद्र में विपक्ष में थी। इन वीडियो में भाजपा तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर हमला करती और केंद्रीय एजंसी के राजनीतिकरण की निंदा करती नजर आ रही है। तृणमूल ने कहा कि भाजपा, उन्हीं पापों की अब स्वयं दोषी है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया कि भाजपा ने स्वीकार कर लिया है कि वह अभिषेक बनर्जी को 'बड़ा खतरा' मानती है और वह उन्हें निशाना बना रही है।

चिटफंड मामले में सीबीआइ ने नगर निकाय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने सनमर्ग वेलफेयर आर्गनाइजेशन से जुड़े चिट फंड घोटाले के मामले में पुलिस ने कोलकाता के पास स्थित हालीशहर नगर निगम के अध्यक्ष राजू साहनी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सीबीआइ ने तलाशी के दौरान 80 लाख रुपए नकद और देसी तमंचा बरामद किया। सीबीआइ ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 30 अक्तूबर 2018 को मामला दर्ज किया था।

'बंद होनी चाहिए मवेशियों की तस्करी'

कोलकाता, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी मामले को लेकर बीरभूम जिले के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद तृणमूल में लगातार विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। सांसद जवाहर सरकार के बाद अब पार्टी के एक विधायक ने कहा है कि मवेशियों की तस्करी हर हाल में बंद होनी चाहिए।

पूर्व बर्दवान के केतुग्राम से विधायक शेख शहनवाज का एक वीडियो वायरल हुआ है, जो गुरुवार रात का बताया जा रहा है। साथ ही इसमें शाहनवाज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मवेशियों की तस्करी लंबे समय से होती आ रही है। इसके प्रमाण जब सामने हैं तो इसे निश्चित तौर पर बंद करना चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई भी गैरकानूनी काम बंद होने ही चाहिए।

खास बात यह है कि के के तुग्राम विधानसभा का प्रभार अनुब्रत मंडल के जिम्मे रहा है, जो फिलहाल मवेशी तस्करी मामले में जेल में हैं। साथ ही ऐसे में तृणमूल विधायक का यह बयान अपने आप में सुर्खियों में है। साथ ही इसके पहले जब सांसद जौहर सरकार ने इसी तरह से बयान दिया था तो पार्टी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय उनके खिलाफ हमलावर हो गए थे और पार्टी में उनके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की मांग की थी।

एकल पीठ का सीबीआइ जांच आदेश बरकरार

कोलकाता, 2 सितंबर (भाषा)।

कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआइ (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) जांच कराने के एकल पीठ के आदेश को शुक्रवार को बरकरार रखा।

प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती मामला

न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने एकल पीठ को जांच की निगरानी करने का निर्देश भी दिया। इसके साथ ही न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में कथित अनियमितताओं की सीबीआइ द्वारा जांच कराने के आदेश को बरकरार रखते हुए खंडपीठ ने कहा कि मामले में धन के लेन-देन की जांच जरूरत पड़ने पर की जाएगी।

इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि 'पश्चिम बंगाल प्राइमरी स्कूल बोर्ड' से चुनिंदा रूप से एक अतिरिक्त अंक का लाभ पाने वाले 269 लोगों को उनकी नौकरी से हटाने का एकल पीठ का आदेश, एकल पीठ के समक्ष मामले के निपटारे तक बरकरार रहेगा।

एसएफआइ ने शिक्षक भर्ती में धांधली के खिलाफ रैलियां निकालीं

कोलकाता, 2 सितंबर (भाषा)।

वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआइ) के सदस्यों ने बंगाल में शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं के विरोध में शुक्रवार को शहर में रैलियां निकालीं और मांग की कि भ्रष्ट आचरण से 'शिक्षा प्रणाली' को बचाया जाए।

एसएफआइ द्वारा दिन के दौरान चार रैलियों का आयोजन किया गया –जो श्यामबाजार, सियालदह, हिंद सिनेमा और हावड़ा स्टेशन से शुरू हुईं और कालेज स्क्वायर पर एकत्रित हुईं। रैली में भाग लेने वालों के हाथ में पोस्टर थे और वे संविधान, देश और शिक्षा प्रणाली की रक्षा करने की मांग कर रहे थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने कालेज स्क्वायर पर एक सभा को संबोधित करते हुए वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस ने दावा किया कि उनकी पार्टी नीत सरकार के दौरान शिक्षकों सहित सरकारी नियुक्तियों में कोई धांधली नहीं हुई थी।

बोस ने कहा कि वाम मोर्चे के शासन के दौरान कभी भी चिट पर लिखी गई सिफारिशों पर नौकरी नहीं दी गई।

बोस ने कहा कि वाम मोर्चे के शासन के दौरान कभी भी चिट पर लिखी गई सिफारिशों पर नौकरी नहीं दी गई। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की कथित करीबी अर्पिता मुखर्जी के स्वामित्व वाले कई फ्लैट से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगभग 50 करोड़ रुपए नकद जब्त करने का जिक्र करते हुए माकपा नेता ने दावा किया कि उन्होंने अपने 83 वर्षों के जीवन काल में इतनी नकदी कभी नहीं देखी।

समयसीमा समाप्त होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ आधार अपलोड करने का काम

कोलकाता, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

अंगनवाड़ी उपभोक्ताओं का आधार नंबर केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। जबकि केंद्र सरकार की ओर से निर्देश दिया गया था कि यह काम 31 अगस्त तक पूरा होना चाहिए।

राज्य के किसी भी जिले में 100 फीसद अपलोड करने का काम पूरा नहीं हुआ है। मालूम हो कि केंद्र के निर्देश के मुताबिक, आधार नंबर अपलोड रहने वाले उपभोक्ताओं को ही रकम प्रदान कीजायेगी। हालांकि इस बारे में समय सीमा में कई बार वृद्धि की गई है।राज्य सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक, 11 जिलों में 90 फीसद से ज्यादा अपलोड का काम पूरा हो चुका है। इसमें बर्दमान, कूचबिहार, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी जिले शामिल हैं। जबकि दक्षिण 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा जैसे जिलों में करीब 90 फीसद अपलोड का काम पूरा हुआ है। कोलकाता में अभी तक 83 फीसद काम पूरा हुआ है। हुगली जिले में भी यही स्थिति है।

औसतन राज्य में 89 फीसद अपलोड का काम पूरा हो गया है। एक अधिकारी ने बताया कि 10 फीसद काम पूरा नहीं होने की वजह यह है कि लोगों के आधार में कई तरह की गड़बड़ी है। जिसकी जांच का काम चल रहा है। समस्या का हल होने के बाद ही यह काम पूरा हो जाएगा । एक अधिकारी ने बताया कि 10 फीसद काम पूरा नहीं होने की वजह यह है कि लोगों के आधार में कई तरह की गड़बड़ी है।

सियालदह मेन शाखा में बंद रहेंगी कई ट्रेनें

कोलकाता, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

शनिवार की रात से लेकर रविवार तड़के तक सियालदह मेन शाखा में कई ट्रेनें बंद रहेंगी। रेलवे की ओर से यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि रेलवे लाइन की मरम्मत के लिए रात 10 बजे से लेकर तड़के छह बजे तक यह ट्रेनें रद्द की गई हैं।

रेलवे के मुताबिक, मरम्मत के दौरान एक जोड़ी सियालदह-कल्याणी सीमांत लोकल ट्रेन, एक जोड़ी सियालदह नैहट्टी लोकल को रद्द कियागया है। इसके साथ ही बैरकपुर-नैहट्टी सेक्शन में दो जोड़ी ट्रेनें रद्द की गई हैं। इसके अलावा नैहट्टी कल्याणी सीमांत लोकल के समय में फेरबदल किया गया है। 4.10 बजाए यह ट्रेन 5.12 बजे चलेगी।

राज्य में बन रहे भारी बारिश के आसार

कोलकाता, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने यहां के कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य में कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं और बाढ़ के हालात भी बनेंगे। मौसम विभाग सूत्रों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मानसून की वजह से दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसकी वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। मानसून की वजह से जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग में तेज बारिश होगी और ये स्थिति तीन से पांच दिन तक रहेगी ।

दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के पहाड़ी इलाकों में जगह-जगह भूस्खलन जबकि मैदानी इलाके जलमग्न हो सकते हैं। ऐसे में शहर के हालात संभालने के लिए प्रशासन को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर महीने में कई राज्यों में सामान्य या उससे अधिक बारिश होगी। मानसून असम सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों को अगले पांच दिनों तक तर करता रहेगा।

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
शिपिंग हाउस, २४५ मदाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई – ४०००२१.
वेबसाइट: www.shipindia.com; Twitter: @shippingcorp; सीआईएन: L63030MH1950GOI008033
टेली.: ९१-२२ २२०२६६६६, २२७७ २०००; फैक्स: ९१-२२ २२०२६९०५
Navratna Company (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified)

एजीएम और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

इस सूचना के द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की ७२वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, २८ सितंबर, २०२२ को १२:०० बजे (भारतीय मानक समय) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए आयोजित की जाएगी:

१	०२.०९.२०२२ को ७२वीं एजीएम की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों के प्रेषण की तिथि (सूचना सहित, वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के लिए निदेशकों की रिपोर्ट संलग्नक के साथ)। वार्षिक रिपोर्ट www.shipindia.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
२	कंपनी की ७२वीं एजीएम और घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक **२४.०९.२०२२ से २८.०९.२०२२ (दोनों दिन शामिल)** तक बंद रहेंगे। लाभांश की रिकॉर्ड तिथि **२३.०९.२०२२** है।
३	रिमोट ई-वोटिंग अवधि – **२५.०९.२०२२ पूर्वाह्न ९:०० बजे (भारतीय मानक समय) से २७.०९.२०२२ शाम ५:०० बजे (भारतीय मानक समय)।**
४	रिमोट ई-वोटिंग के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए कट-ऑफ-डेट **शुक्रवार, २३.०९.२०२२** है।
५	कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के माध्यम से एजीएम के सूचना में निर्धारित प्रस्तावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे इस दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग व्यवस्था वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य इसे https://www.evoting.nsdl.com पर शेयरधारकों/ सदस्यों के लॉगिन के तहत रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके एक्सेस कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN यानी १२१६६६ प्रदर्शित होगा। एजीएम से पहले या उसके दौरान ई-वोटिंग/सहायता के संबंध में किसी भी प्रश्न या मुद्दों के मामले में, आप एजीएम की सूचना देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक से १८००१०२०९९० एवं १८००२२४४३० पर संपर्क कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ईमेल कर सकते हैं।
६	एजीएम की ई-सूचना के प्रेषण के बाद शेयर प्राप्त करने वाला और २३.०९.२०२२ को शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति, 'Financials → Financial Results → Annual Reports' खंड के तहत ७२वीं वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी के लिए एससीआई की वेबसाइट www.shipindia.com पर जा सकता है।
७	ई-वोटिंग के तरीके, ईमेल आईडी / बैंक खाते को अपडेट करने, वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, लाभांश पर टीडीएस की प्रयोज्यता के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप 'Investors → Information for Shareholders → Notices' के तहत www.shipindia.com पर जा सकते हैं।

हस्ता/-
निदेश मंडल के आदेश से
कृते भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
श्रीमती स्वप्निता विकास यादव
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : ०२.०९.२०२२

कार्गो मंजिल तक पहुँचाए. जीवन को राह दिखाए.

SHYAM METALICS AND ENERGY LIMITED
CIN: L40101WB2002PLC095491
Regd. Office: Trinity Tower, 7th floor, 83, Topsia Road, Kolkata-700046
Phone: 033-4016 4080, Fax: 033-4016 4025
Email: compliance@shyamgroup.com, Website: www.shyammetalics.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY 20TH ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE FOR DIVIDEND AND INFORMATION ON REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting (the "AGM") of Shyam Metalics and Energy Limited (the "Company") will be held on **Monday, 26th September, 2022 at 3:00 P.M.** through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013, Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA") General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 02/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021 and May 5, 2022 respectively (hereinafter, collectively referred as the "MCA Circular") and also read with the SEBI Circulars No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 respectively (hereinafter, collectively referred as the "SEBI Circulars" and together with the MCA Circulars referred as the "Circulars") permitted to hold the AGM through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue.

In accordance with the Circulars, the Notice convening the AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2022 has been sent only through e-mails to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent (the "RTA") i.e., M/s. KFin Technologies Limited or the Depository Participant(s) and holding equity shares of the Company as on Friday, August 26, 2022.

The Notice and the Annual Report are available on the website of the Company viz., and has also been forwarded to the Stock Exchanges where Equity Shares of the Company are listed, enabling them to disseminate the same on **their respective websites viz., www.nseindia.com and www.bseindia.com.** The Notice shall also be available on the e-Voting website of the agency engaged for providing e-Voting facility, i.e., National Securities Depository Limited ("NSDL"), viz., www.evoting.nsdl.com. Any Member desirous of obtaining hard copy of the Annual Report can send a request for the same to the Company at compliance@shyamgroup.com mentioning Folio No./DP ID/Client ID.

Members are also informed hereby that:

1 Pursuant to Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide e-Voting facilities through NSDL to its Members, in respect of the businesses to be transacted at the AGM. The manner and instructions to cast votes through remote e-Voting as well as through e-Voting system during the Meeting have been provided along with the Notice.
2 The businesses set out in the Notice shall be transacted through e-Voting only. The Members, whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on **Monday, September 19, 2022, being the cut-off date,** shall be entitled to avail the e-Voting facility. Once vote(s) on Resolution(s) are cast by any Member, the same cannot be changed subsequently. The remote e-Voting will commence on **Friday, September 23, 2022 (9:00 A.M. IST) and end on Sunday, September 25, 2022 (5:00 P.M. IST).** Thereafter, the module of remote e-Voting shall be disabled by NSDL.
3 Members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-Voting, shall be eligible to exercise their voting rights during the AGM through e-Voting system **via www.evoting.nsdl.com**. Members who have exercised their voting rights by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC or OAVM but shall not be entitled to cast their votes again during the AGM.
4 Any person, who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e., Monday, September 19, 2022 may obtain the login Id and password for e-Voting, by sending a request to NSDL at **evoting@nsdl.co.in or to the Company at compliance@shyamgroup.com.** Members who are already registered with NSDL for remote e-Voting can use their existing User Id and Password for e-Voting.
5 All documents referred to in the Notice and the Explanatory Statement thereto shall be made available for inspection by the Members of the Company, without payment of fees, upto and including the date of AGM. Members desirous of inspecting the same may send their requests at **compliance@shyamgroup.com** from their registered e-mail addresses mentioning their names and folio numbers / demat account numbers.
6 Pursuant to Section 91 of the Act, Rule 10 of the said Rules and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Registers of the Company shall remain closed from **Tuesday, September 20, 2022 to Monday, September 26, 2022 (both days inclusive),** for the purpose of the AGM and payment of dividend.
7 The Dividend of Rs. 2.70/- per equity shares (27%) on the face value of Rs. 10/- each for the year ended on 31st March, 2022 as recommended by the Board of Directors and if declared at the AGM, will be paid by the Company through permitted modes within prescribed time limit to those members whose name appear in the register of members **as on the Record date i.e. Monday, 19th September, 2022.**
8 Pursuant to the changes introduced by the Finance Act, 2020 in the Income-tax Act, 1961 (the "IT Act") w.e.f. April 1, 2020, the dividend paid or distributed by a Company shall be taxable in the hands of the shareholders. Accordingly, in compliance with the said provisions, the Company shall make the payment of dividend after necessary deductions of tax at source (TDS). The withholding tax rates would vary depending on the residential status of every shareholder and the requisite legitimate documents submitted by them to the Company. Members are hereby requested to update their details like Residential Status, PAN, and category as per the I.T. Act with their respective Depository Participants or in case of shares held in physical mode, the Company / the RTA.
9 In case shareholders have not registered / updated their email address with the Depositories / Share Transfer Agent, they are requested to kindly follow the below mentioned instructions for updating the E-mail IDs and to enable the company to provide a copy of Annual Report incorporating Notice of the AGM and to cast their vote on the respective Resolutions.

Instructions to register / update the E-mail ID:

Physical Holding	**Shareholders are requested to register / update the same by submitting duly filled and signed Form ISR-1 with the RTA, M/s. Kfin Technologies Ltd at einward.ris@kfintech.com**
Demat Holding	**Please contact your Depository Participants (DP) and register your email address.**

In case of any queries in registering the email address, shareholders may write to **compliance@shyamgroup.com.**

10 In case of any queries / grievances relating to e-Voting, Members may refer to "Frequently Asked Questions on e-Voting (For Shareholders).pdf" and "e-Voting Manual - Shareholder.pdf" available at the "Download" section of NSDL e-Voting website, i.e., www.evoting.nsdl.com or call on Toll Free Nos.: 1800 1020 990 and 1800 224 430 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager of NSDL at Telephone Nos.: (022) 24994360 / (022) 24994545 or at e-mail id: evoting@nsdl.co.in or contact at NSDL, 'Trade World', 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013. Members holding securities in demat mode with CDSL, can call at Telephone Nos.: (022) 23058738 / 23058542-43 or at e-mail id: helpdesk.evoting@cdslindia.com. For any further assistance, Members may also contact Mr. Birendra Kumar Jain, Company Secretary, Shyam Metalics and Energy Limited at Telephone No. (033) 40175029 or at the e-mail ID compliance@shyamgroup.com.

For Shyam Metalics and Energy Limited
Sd/-
Birendra Kumar Jain
Company Secretary
ICSI Membership No. ACS 8305

Place: Kolkata
Date: September 02, 2022

खबर कोना

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक जिले में बाढ़ की वजह से घर छोड़कर आई एक महिला रैनबसेरे में अपने बच्चों के साथ।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ अंतिम चरण में

लंदन, 2 सितंबर (भाषा)।

कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस के बीच दौड़ शुक्रवार को अंतिम चरण में है। जिसमें पार्टी के सदस्य अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव के लिए अंतिम रूप से मतदान करेंगे। सुनक (42) और ट्रस (47) कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 1,60,000 सदस्यों के मत पाने और उन्हें प्रभावित करने के लिए कई बार आमने-सामने की बहस कर चुके हैं। भारतीय मूल के पूर्व मंत्री ने अपने अभियान में तत्काल प्राथमिकता के रूप में बढ़ती मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने की बात कही है। वहीं, विदेश मंत्री ट्रस ने वादा किया है कि यदि वह प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं तो कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही करों में कटौती करने का आदेश जारी करेंगी। सुनक अंतिम दो उम्मीदवार चुनने के लिए पार्टी के सांसदों द्वारा किए गए मतदान में जहां ट्रस से आगे थे।

डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक लोकतंत्र के लिए खतरा : बाइडेन

वाशिंगटन, 2 सितंबर (भाषा)।

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वह और उनके समर्थक अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। बाइडेन ने अमेरिकियों से उन चरमपंथियों का सामना करने का आह्वान किया, जो सत्ता की चाह में राजनीतिक हिंसा की लपटों को हवा देते हैं। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नवंबर में होने हैं। गुरुवार को फिलाडेल्फिया में अपने संबोधन में बाइडेन ने कहा कि आज समानता और लोकतंत्र खतरे में है।

यूक्रेन के परमाणु संयंत्र के पास लड़ाई जारी

जपोरिज्जिया (यूक्रेन), 2 सितंबर (एपी)।

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के विशेषज्ञों द्वारा विशाल संरचनात्मक क्षति को लेकर चिंता व्यक्त किए जाने के एक दिन बाद पूर्वी यूक्रेन के रूस-नियंत्रित क्षेत्र में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास शुक्रवार को भीषण लड़ाई जारी रही। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जिस जिले में जपोरिज्जिया परमाणु संयंत्र है, वहां गोलाबारी जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा कि रूस की गोलाबारी में नीपर नदी के दूसरे तट पर निकोपोल क्षेत्र में घर, गैस पाइपलाइन और अन्य बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए। आइएईए के निरीक्षकों की टीम मार्ग में गोलाबारी के बीच संयंत्र की सुरक्षा में मदद करने के लिए गुरुवार को जपोरिज्जिया संयंत्र तक पहुंचने के लिए सीमा रेखा को पार कर गई।

मुरुग मठ के महंत को पांच सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

चित्रदुर्ग/बेंगलुरु, 2 सितंबर (भाषा)।

कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित मुरुग मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुग शरणारु को दो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में शुक्रवार को, पांच सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। महंत को बृहस्पतिवार रात को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि महंत पर लगे आरोप 'गंभीर' हैं। आरोपी को शुक्रवार को एक अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने पांच दिन की हिरासत की मांग की। महंत ने भगवा कपड़ों के ऊपर सफेद वस्त्र पहना था और उन्हें अदालत में वीलचेयर पर लाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय हुआ विस्फोट

अफगानिस्तान : हेरात शहर की मस्जिद में धमाका, 18 की मौत

हेरात, 2 सितंबर (एपी)।

उत्तरी अफगानिस्तान के हेरात शहर में शुक्रवार को एक मस्जिद में धमाका हुआ। इस धमाके में एक प्रमुख मौलवी समेत कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई जबकि 21 अन्य घायल हो गए।

तालिबान के अधिकारियों ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि हेरात शहर की गुजारगाह मस्जिद में शुक्रवार दोपहर की नमाज के समय यह विस्फोट हुआ। गौरतलब है कि जुमे की नमाज के दौरान आमतौर पर अधिक भीड़ होती है। इस विस्फोट में मुजीब-उल रहमान अंसारी की भी मौत हो गई, जो एक प्रमुख मौलवी थे। पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान की पश्चिम-समर्थित सरकारों की आलोचना के लिए अंसारी को पूरे अफगानिस्तान में पहचाना जाता था। अंसारी को तालिबान का करीबी समझा जाता है, जिसने विदेशी बलों के वापस जाने के बाद पिछले साल देश की सत्ता पर नियंत्रण हासिल किया था। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने धमाके में अंसारी की मौत की पुष्टि की है। वहीं एक हेरात एंबुलेंस सेंटर के एक अधिकारी मोहम्मद दाउद मोहम्मदी ने कहा कि एंबुलेंस से 18 मृत और 21 घायलों को अस्पताल लाया गया है। शुक्रवार के इस धमाके की अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

तालिबान के अधिकारियों ने बताया कि हेरात शहर की गुजारगाह मस्जिद में शुक्रवार दोपहर की नमाज के समय यह विस्फोट हुआ। *हादसे* में मुजीब-उल रहमान अंसारी की भी मौत हो गई, जो एक प्रमुख मौलवी थे।

सू की को तीन साल की सजा

बैंकाक, 2 सितंबर (एपी)।

म्यांमा की एक अदालत ने शुक्रवार को देश की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को चुनावी धोखाधड़ी में संलिप्तता का दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई। सैन्य शासित देश में सू की को पहले ही कई अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है और 17 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे में इस सजा के बाद उन्हें अब और अधिक समय जेल में काटना होगा।

इससे सू की की 'नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी पार्टी' का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। सेना ने देश में 2023 में नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की है। सू की की पूर्व सरकार के दो वरिष्ठ सदस्यों को भी मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि एक फरवरी 2021 को म्यांमा की सेना ने देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और सू की तथा म्यांमा के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया था। सू की की पार्टी ने पिछले आम चुनाव में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन सेना का कहना है कि चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई।

आज श्रीलंका लौटेंगे गोटबाया

कोलंबो, 2 सितंबर (भाषा)।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे शनिवार तड़के थाईलैंड से स्वदेश लौटेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की। राजपक्षे श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच उनके तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर महीनों से जारी विरोध-प्रदर्शनों के नौ जुलाई को हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद 13 जुलाई को देश छोड़कर भाग गए थे। उस समय प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति आवास सहित कई अन्य सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया था।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राजपक्षे शनिवार सुबह श्रीलंका लौटेंगे। हालांकि, उनकी उड़ान के बारे में अभी कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह कोलंबो के पूर्वी उपनगर मिरिहाना स्थित अपने निजी आवास में ठहरेंगे या नहीं। राजपक्षे पहले श्रीलंका वायुसेना के विमान के जरिए कोलंबो से मालदीव भागे थे। मालदीव से वह सिंगापुर रवाना हुए थे, जहां से उन्होंने 14 जुलाई को अपना इस्तीफा भेजा था।

अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति की हत्या की कोशिश नाकाम

हमलावर ने तान दी थी पिस्तौल, लेकिन चली नहीं

ब्यूनस आयर्स, 2 सितंबर (एपी)।

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने बताया कि देश की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के घर के बाहर उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। एक हमलावर ने उन पर पिस्तौल तान दी थी, लेकिन वह चली नहीं।

अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार रात हुई घटना के तुरंत बाद संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया गया। राष्ट्रपति ने घटना के बाद एक राष्ट्रीय प्रसारक से कहा कि एक व्यक्ति ने उनके सिर पर (गुरुवार रात) हथियार ताना। उन्होंने कहा कि गोली नहीं चली, जबकि उसने ट्रिगर खींच दिया था। उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज 2007 से 2015 तक देश की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उपराष्ट्रपति को कोई चोट नहीं आई है। संदिग्ध हमलावर उनके समर्थकों के बीच खड़ा था, जिसे घटना के तुरंत बाद पकड़ लिया गया। मौके पर मौजूद जिना दे बई ने बताया कि उन्होंने ट्रिगर खींचने की आवाज सुनी थी। उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मियों के संदिग्ध को पकड़ने तक उन्हें एहसास नहीं हुआ था कि वह किसी हथियार की आवाज है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने इसे 1983 में देश में लोकतंत्र बहाल होने के बाद की अभी तक की सबसे गंभीर घटना बताया। घटना ऐसे समय में हुई है, जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ उनके 2007-2015 के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कथित कृत्यों के संबंध में मुकदमे चल रहे हैं।

स्थानीय टेलीविजन चैनल पर प्रसारित घटनास्थल के वीडियो में फर्नांडीज अपने घर के बाहर समर्थकों से घिरे अपने वाहन से बाहर निकलती दिख रहीं है। तभी एक व्यक्ति पिस्तौल जैसी दिखने वाली कोई एक वस्तु लिए नजर आ रहा है। हालांकि, उपराष्ट्रपति वहां से निकलने में कामयाब रहीं। वीडियो में मौके पर मौजूद उपराष्ट्रपति के समर्थक भी स्तब्ध नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित असत्यापित वीडियो में हथियार फर्नांडीज के चेहरे को लगभग छूता नजर आ रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि हमलावर की पहचान ब्राजील के नागरिक फर्नांडो आंद्रे सबाग मोंटिएल के तौर पर हुई है। उसका कोई आपराधिक रेकार्ड नहीं है। उसके पास .32-कैलिबर बर्सा पिस्तौल थी। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के साथ एकजुटता व्यक्त करने और लोगों को इस घटना से उबरने का समय देने के लिए शुक्रवार को छुट्टी की घोषणा की है। गौरतलब है कि एक अभियोजक ने पिछले सप्ताह सार्वजनिक कार्यों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में फर्नांडीज को 12 साल की सजा देने की मांग की थी, जिसके बाद से उपराष्ट्रपति के समर्थक उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए उनके घर के आसपास सड़कों पर जमा होते रहे हैं। सरकार के अधिकारियों ने इस घटना को हत्या का प्रयास बताया है।

वित्त मंत्री सर्जियो मास्सा ने कहा कि जब विचारों पर नफरत व हिंसा थोपी जाती है, तो समाज बर्बाद हो जाते हैं और आज जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यह हत्या का प्रयास है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज की सरकार में मंत्रियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वे उपराष्ट्रपति की हत्या के प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं।

उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के सिर पर पिस्तौल ताने हुए हमलावर (घेरे में)।

शुभेंदु की फरियाद सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

ममता बनर्जी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका को दूसरे हाईकोर्ट में भेजने की मांग वाली भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालयों के इस विकल्प की अनुमति नहीं दे सकती। जिस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, मामले की सुनवाई वहीं होगी।

पीठ ने अधिकारी को चुनाव याचिकाकर्ता के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता दे दी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका को स्थानांतरित करने से संदेश जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय में विश्वास की कमी जता रहा है। हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने माना कि उच्च न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्र के मुकदमे पर नियंत्रण रखने में सक्षम होना चाहिए।

अधिकारी ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के माध्यम से पीठ को अपनी दुर्दशा से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में चुनावी याचिका की सुनवाई के लिए माहौल अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद एक पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि क्योंकि उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति में से एक का विरोध किया था, इसलिए उन्हें एक संबंधित मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए। जिन न्यायाधीशों ने अधिकारी के अनुकूल राहत प्रदान की है, उन्हें राज्य प्रशासन का कोप भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन्होंने पश्चिम बंगाल में वर्तमान सरकार के प्रतिकूल आदेश पारित किए हैं। वहां जो हो रहा है, वह चिंताजनक है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य न्यायाधीशों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं कि चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान अनुकूल माहौल बनाए रखा जाए। उनके कंधे इससे निपटने के लिए काफी चौड़े हैं। साल्वे ने जवाब दिया कि उन्होंने न्यायाधीशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है।

पीठ ने अधिकारी को चुनाव याचिकाकर्ता के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता दे दी।

इंतजार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती संसद की 62वीं स्थापना वर्षगांठ पर प्रस्तुति देने की प्रतीक्षा में तिब्बती बच्चे।

सत्ता में आए तो एमएसपी पर खरीदेंगे फसलें : केजरीवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में उनकी सरकार बनने पर किसानों की पांच फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का वादा किया है।

उन्होंने कहा कि अगले साल से अगर बाजार में गेहूं, चावल, कपास, चना व मूंगफली के दाम एमएसपी से कम रहे तो सरकार इन पांच फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। वे शुक्रवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे थे और एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गुजरात में सरकार बनने पर दिल्ली की तर्ज पर गुजरात में भी फसल बर्बाद होने पर 20 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा देने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि हर बार सरकार फसल की एमएसपी जारी तो कर देती है, लेकिन बाजार में कोई एमएसपी पर फसल खरीदता नहीं है। अगर कोई किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेचना चाहता है, तो सरकार उसकी फसल खरीदेगी। वो सीधे सरकार को एमएसपी पर अपनी फसल भेज सकता है। अगले साल से अगर बाजार में पांचों फसलों का दाम एमएसपी से कम मिल रहा है।

रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विकसित होंगे 'माडल विद्यार्थी क्लब'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) देश के तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों में रुचि, रचनात्मकता एवं नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने की योजना (स्पाइसेज) के तहत 'विद्यार्थी क्लबों' को 'माडल क्लब' के रूप में विकसित करेगी।

इसके तहत विविध प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के कार्यों, रुचियों, कल्पनाशक्ति, नवाचार एवं नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि इसके तहत एआइसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से एक मौजूदा विद्यार्थी क्लब को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आनलाइन प्रस्ताव मांगा गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विद्यार्थी क्लबों को माडल क्लब में विकसित करने के लिए एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। संस्थान इसके लिए 30 सितंबर, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

एआइसीटीई ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थी क्लबों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसी साल विद्यार्थियों में रुचि, रचनात्मकता एवं नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने की योजना (स्पाइसेज) बनाई थी। योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी क्लबों को संस्थान के अन्य क्लबों के लिए माडल के रूप में काम करना चाहिए। योजना के मसौदे के अनुसार इसके तहत एआइसीटीई ऐसे संस्थानों के प्रस्तावों को मंजूरी देगी, जिनकी स्थापना के कम से कम पांच साल पूरे हो गए हों। एक संस्थान से क्लब के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा, जिनमें कम से कम 50 विद्यार्थी सदस्य हों। संस्थान को भी क्लब के लिए एक लाख रुपए का योगदान देना होगा। इसमें कहा गया है कि क्लब का अपना वेबपेज होना चाहिए, जिसमें उसकी विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई हो। इस उद्देश्य के लिए एक संयोजक बनाया जाएगा, जो पूर्णकालिक शिक्षक होगा और उसे कम से कम 10 सालों का शिक्षण अनुभव होना चाहिए।

पूर्वानुमान युवा आबादी में 2011 से गिरावट से नामांकन में आ रही कमी : एनसीईआरटी

स्कूलों में नामांकन में आएगी गिरावट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के एक अध्ययन में यह पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है कि 2011 से शुरू होकर 2025 तक स्कूलों में विद्यार्थियों के सकल नामांकन में 14 फीसद से अधिक गिरावट आएगी। वहीं, लड़कों की तुलना में लड़कियों के दाखिले में दो फीसद कमी आएगी। एनसीईआरटी के शैक्षणिक सर्वेक्षण प्रकोष्ठ (ईएसडी) के अध्ययन में कहा गया है कि 5-10 साल के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले में कोई बदलाव नहीं आएगा, जबकि 2023-24 के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का दाखिला स्थिर हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दाखिला आबादी से जुड़ा होता है,

ऐसे में 6-11, 11-14 और 14-16 साल के आयु वर्ग के बच्चों की आबादी में गिरावट का प्रभाव हर वर्ग में दाखिले पर दिखाई देता है।

'2025 तक स्कूलों में दाखिले का पूर्वानुमान एवं लक्षण' शीर्षक से रिपोर्ट में एनसीईआरटी द्वारा कराए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) और शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों को लिया गया है। अध्ययन में 21 राज्यों के एनएएस रिपोर्ट पर विचार किया गया है और 2011 के बाद से आबादी को ध्यान में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में आंकड़ों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है और कुछ आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे। 2011 तक प्रारंभिक शिक्षा के स्तर तक नामांकन ऊपर की ओर गया, लेकिन 2011 के बाद से दाखिले में गिरावट आई और यह 2025 तक तक जारी रहेगा। इसमें कहा गया है कि 2011 से 2025 तक नामांकन में गिरावट की दर 14.37 फीसद रहेगी और इसमें लड़कों के दाखिले में 13.28 फीसद और लड़कियों के दाखिले में 15.54 फीसद गिरावट आएगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़के एवं लड़कियों के नामांकन में गिरावट 2016 से शुरू हुई और सकल नामांकन गिरावट 9.47 फीसद रही। इसमें लड़कों के दाखिले में 8.07 फीसद और लड़कियों के नामांकन में 10.94 फीसद गिरावट आई।

'नवजात की मृत्यु पर महिला कर्मी को 60 दिन का विशेष अवकाश'

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

आदेश में कहा गया है कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु से मां को पहुंचने वाली भावनात्मक चोट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है क्योंकि ऐसी घटनाओं का मां के जीवन पर बहुत गहरा प्रभव पड़ता है। डीओपीटी ने बताया कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु होने पर अवकाश/मातृत्व अवकाश के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध करने वाले कई आवेदन उसे मिले हैं। विभाग ने आदेश में कहा, 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया है। मृत नवजात शिशु के जन्म या प्रसव के तुरंत बाद उसकी मौत से पहुंचने वाले सदमे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को ऐसी स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया गया है।' डीओपीटी ने अपने आदेश में कहा है, अगर केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी पहले ही मातृत्व अवकाश ले चुकी है और मृत शिशु पैदा होने या शिशु की मृत्यु होने तक उसका अवकाश जारी है तो, ऐसा होने की तारीख तक कर्मचारी द्वारा लिए गए अवकाश को उसके पास मौजूद अन्य किसी अवकाश में तब्दील किया जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार के मेडिकल प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

'आठ साल में मनरेगा पर खर्च किए पांच लाख करोड़'

हैदराबाद, 2 सितंबर (भाषा)।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीते आठ वर्षों में केंद्र ने मनरेगा योजना पर पांच लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिनमें से 20 फीसद कोविड महामारी के दौरान व्यय किए गए।

तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में गुरुवार को सीतारमण ने कहा कि बीते आठ वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य को 20 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी अवधि में पूरे देश में पांच लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से 20 फीसद से अधिक 2020-21 के दौरान कोविड-19 के प्रकोप के वक्त खर्च किए गए। इसमें अहम मुद्दा यह है कि यदि पैसा ठीक से खर्च नहीं होने की शिकायतें आती है या आडिट रिपोर्ट में कोई टिप्पणी होती है तो तो सर्वे दल (किसी भी राज्य में) आएंगे। ऐसे आरोप लगाए गए थे कि सर्वे दलों को योजना को रोकने के लिए भेजा जा रहा है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कोई विसंगतियां होने पर सर्वे दलों को उनमें सुधार करने के लिए भेजा जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में योजना में अनेक खामियां थीं, जिन्हें मोदी सरकार ने दूर किया और इसे अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए लागू किया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि के चंद्रशेखर राव की सरकार राज्य विधानसभा को सूचित किए बगैर और बजट में उल्लेख किए बगैर ऋण ले रही है। सीतारमण ने कहा कि किसान आत्महत्या के मामले में राज्य चौथे पायदान पर है।

लुफ्थांसा के पायलटों ने की हड़ताल, यात्री परेशान

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

पायलटों की हड़ताल के कारण लुफ्थांसा एयरलाइन की दो उड़ानें रद्द होने के बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) हवाई अड्डे के टर्मिनल तीन पर शुक्रवार को सैकड़ों यात्री फंसे रहे और अफरातफरी का माहौल व्याप्त हो गया। पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को आइजीआइ हवाई अड्डे के टर्मिनल तीन पर लगभग सात सौ यात्री फंस गए। पुलिस के अनुसार, फंसे हुए यात्रियों के परिजन और रिश्तेदारों समेत सौ से ज्यादा लोग हवाई अड्डे के बाहर एकत्र होकर पैसे वापस मांगने तथा वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग करने लगे। विमानन कंपनी ने कहा, 'लुफ्थांसा को शुक्रवार के लिए फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख की आठ सौ उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। गुरुवार के लिए भी एकल उड़ानों को रद्द किया गया है।' कंपनी ने कहा, 'आगामी सप्ताहांत और यूरोप के कुछ हिस्सों में छुट्टियां समाप्त होने के मद्देनजर लगभग एक लाख तीस हजार यात्री प्रभावित होंगे। लुफ्थांसा शीघ्रातिशीघ्र उड़ानें सामान्य करने का प्रयास कर रही है। इसके बावजूद, हड़ताल की वजह से इस शनिवार और रविवार को भी उड़ानें रद्द हो सकती हैं।'

हवाईअड्डे पर फंसे लोगों में कई छात्र शामिल हैं जिनकी कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। परेशान यात्री विमानतल पर अपने सामान के साथ बैठकर 'हमें न्याय चाहिए' का नारा लगाने लगे। यात्रियों ने कहा कि हवाई अड्डे के अधिकारियों की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं की गई।

सूचकांक 37 अंक मजबूत

मुंबई, 2 सितंबर (भाषा)।

घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को उतार-चढ़ाव के बीच बीएसई सूचकांक लगभग 37 अंक की बढ़त में रहा। वैश्विक वृद्धि में नरमी और विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत दर बढ़ाने को लेकर चिंता के बीच बाजार में उतार-चढ़ाव रहा।

कारोबारियों ने कहा कि रुपए की विनिमय दर में गिरावट व विदेशी पूंजी की निकासी से भी निवेशक जोखिम लेने से बचे। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सूचकांक कारोबार के दौरान काफी समय तक कभी लाभ में और कभी नुकसान में रहा। अंत में यह 36.74 अंक यानी 0.06 फीसद की बढ़त के साथ 58,803.33 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 3.35 अंक यानी 0.02 फीसद की मामूली गिरावट के साथ 17,539.45 अंक पर बंद हुआ।

सूचकांक के शेयरों में एचडीएफसी लि सबसे अधिक 1.75 फीसद लाभ में रहा। इसके अलावा आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे।

वेतन के मुद्दे पर अलायंस एअर के पायलटों की हड़ताल

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

विमानन कंपनी अलायंस एअर के पायलटों का एक वर्ग वेतन के मुद्दे को लेकर हड़ताल पर चला गया है। इसके कारण एअरलाइन के कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सरकार के स्वामित्व वाली अलायंस एअर एटीआर विमानों का परिचालन करती है। कंपनी के वेबसाइट के अनुसार, अलायंस एअर प्रतिदिन देशभर में 48 गंतव्यों के लिए 100 उड़ानों का परिचालन करती है।

कोविड-19 महामारी से पहले एअरलाइन 62 गंतव्यों पर अपनी सेवाओं का संचालन कर रही थी। सूत्रों ने बताया कि वेतन के मुद्दों को लेकर पायलटों का एक वर्ग हड़ताल पर चला गया है।

पायलटों की मांगों में से एक उनके वेतन को महामारी के पूर्व स्तर पर बहाल करना है।

एक सूत्र ने कहा कि महामारी के मद्देनजर वेतन में 60 फीसद की कटौती की गई थी, जो अब तक पूरी तरह से बहाल नहीं की गई है।

सूत्रों के अनुसार, कंपनी प्रबंधन जल्द ही पायलटों के वेतन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगा।

आग लगने की घटनाओं के बाद ई-वाहन बैटरी प्रावधान बदलेंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई वाहन) में बार बार हो रही आग लगने की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने वाहनों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी के प्रावधान बदलने का निर्णय लिया है। प्रावधानों में बदलाव इस मामले में बनी विशेष समिति की सिफारिश के आधार पर किया जा रहा है और इस प्रावधानों के माध्यम से केंद्र सरकार ने प्रयोग की जा रही बैटरी की क्षमता बढ़ाने की पहल की है। इसके लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय ने एक प्रारूप तैयार किया गया है और आम जनता से सुझाव मांगे हैं।

ई वाहनों में इस साल की शुरुआत में ही बड़ी संख्या में आग लगने के मामले सामने आए थे और गर्मियां बढ़ने के साथ इन मामलों की संख्या भी बढ़ गई थी। इसके बाद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एक विशेष समिति का गठन किया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह समिति टाटा नरसिंह राव (निदेशक, एआरसी, हैदराबाद) की अध्यक्षता में बनाई थी। समिति की रिपोर्ट के बाद ही केंद्र सरकार ने बैटरी संबंधी मौजूदा नियमों में बदलाव का प्रारूप तैयार किया है। विशेषज्ञ समिति ने एक अक्तूबर, 2022 से नए बैटरी प्रावधान लागू करने की सिफारिश की है। संशोधनों में बैटरी सेल, बीएमएस, आन-बोर्ड चार्जर, बैटरी पैक का प्रारूप, आंतरिक सेल में शार्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रसार आदि से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एल श्रेणी (चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन) के मोटर वाहनों की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। साथ ही एम श्रेणी (यात्रियों को ले जाने वाली कम से कम चार पहिया मोटर गाड़ी) और एन श्रेणी (माल ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन, जो माल के अलावा लोगों को भी ले जा सकता है) के मोटर वाहनों की अलग आवश्यकताएं होती है।

जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को नोटिस जारी कर दिया। न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश राय की पीठ ने याचिका को इसी विषय से संबंधित दूसरी लंबित याचिका के साथ नत्थी करने का आदेश भी दिया है। याचिका अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने दाखिल की है। इससे पहले आठ अगस्त को धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को भी मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया था। अपनी याचिका में देवकी नंदन ठाकुर ने कहा है कि लोगों को साफ हवा, पानी, खाना, स्वास्थ्य और रोजगार हासिल करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कानून वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता है।

याचिका में कहा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस और कारगर कानून न होने की सूरत में अदालत विधि आयोग को निर्देश दे कि दूसरे विकसित देशों में जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को देखने के बाद भारत के लिए भी वह उचित कानून बनाने की दिशा में अपने सुझाव और सिफारिश दे। इससे पहले 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर अदालत ने यह कदम उठाया था। याचिका में उपाध्याय ने कहा था कि आबादी का विस्फोट बम से भी ज्यादा घातक है।

अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में मांग की है कि केंद्र सरकार आबादी नियंत्रण के उपायों को देश में लागू करे। केंद्र सरकार को सरकारी नौकरी, सब्सिडी और सहायता पाने के लिए दो बच्चों की नीति को लागू करना चाहिए।

जे.के. कॉटन लिमिटेड

सीआईएन : U17111UP1924PLC000275
पंजीकृत कार्यालय : कमला टावर, कानपुर–208001, उ.प्र. (इण्डिया)
फोन : +91 512 2371478–81, फैक्स : +91 512 2332665
ई–मेल : abhishek.pandey@jkorg.co.in वेबसाइट : www.jkcotton.com

99वीं वार्षिक आम सभा व पुस्तक बंद होने की जानकारी

कोविड–19 महामारी के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, दिनांक 5 मई, 2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021 और दिनांक 5 मई, 2022 के परिपत्र ('परिपत्रों') द्वारा एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('VC')/अन्य ऑडीओ विजुअल मीन्स ('OAVM') के माध्यम से वार्षिक आम सभा ('AGM') आयोजित करने की अनुमति दी। इन परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में AGM के नोटिस में बताये जाने वाले कारोबार को संपादित करने के लिये जे के कॉटन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 99 वीं AGM VC/OAVM के माध्यम से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को दोपहर 02:00 बजे आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट के साथ AGM के नोटिस केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जायेगी, जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('DP') या कंपनी के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jkcotton.com पर, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगें। सदस्य केवल VC/OAVM के माध्यम से AGM में उपस्थित होने और भाग लेने में सक्षम होंगे। AGM में शामिल होने के निर्देश AGM के नोटिस में प्रदान किये जायेगें और VC/OAVM के माध्यम से AGM में शामिल होने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जायेगी।

कंपनी अपने सदस्यों को AGM के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा के साथ–साथ AGM के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर अपने वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए अपने सदस्यों को दूरस्थ ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। कंपनी ने सदस्यों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए CDSL की सेवाएं ली हैं। इस संबंध में विस्तृत निर्देश AGM के नोटिस का हिस्सा बनेंगे।

जिन सदस्यों के ई–मेल पते DP या कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने ई–मेल पते पंजीकृत करायें:

1– फिजिकल शेयरधारकों के लिए: कृपा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट (आगे और पीछे) की स्कैन कॉपी, पैन (पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) जैसे आवश्यक विवरण कंपनी को abhishek.pandey@jkorg.co.in पर ईमेल में जमा कर दे।

2. डीमैट शेयरधारकों के लिए–कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपडेट करे। यह ई–वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमो के तहत एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्य के रजिस्टर और शेयर अन्तरण रजिस्टर शुक्रवार 23 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 तक (दोनों दिन सम्मिलित) AGM के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड की आज्ञानुसार
हस्ता0/–
(अभिषेक सिंघानिया)
प्रबन्ध निदेशक

स्थानः कानपुर
दिनांकः 02.09.2022

DELHIVERY
डेल्हीवरी लिमिटेड

(पूर्व नाम डेल्हीवरी प्राइवेट लिमिटेड)
सीआईएनः L63090DL2011PLC221234

वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वाली 11वीं वार्षिक आम बैठक से सम्बन्धित सूचना

सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम की सूचना ("**सूचना**") में निर्धारित व्यवसाय(यों) के लेन-देन के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") के समस्त प्रयोज्य प्रावधानों, उसके तहत निर्मित नियमों एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा इस सम्बन्धि जारी अनुगामी परिपत्रों, नवीनतम 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 एवं इस सम्बन्ध जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से "**परिपत्र**" सम्बन्धित) के अनुपालन में डेल्हीवेरी लिमिटेड ("**कम्पनी**") की 11वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) पर आयोजित की जायेगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के लिए की जायेगी।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 ("**वार्षिक रिपोर्ट**") उचित समय पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टीसिपेन्ट्स ("**डीपी**") के साथ पंजीकृत हैं। यह कम्पनी की वेबसाइट **www.delhivery.com**, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर, कम्पनी के डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड **https://www.evoting.nsdl.com/**तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("**लिंक इनटाइम**") की वेबसाइट **www.linkintime.co.in** पर भी उपलब्ध होगा। वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना की प्रतियां इसके लिए निवेदन करने वाले सदस्यों के पास भेज दी जायेंगी।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका :

सदस्य सूचना में निर्धारित व्यवसाय(यों) पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("**ई-वोटिंग**") के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। अभौतिक मोड, भौतिक मोड में शेयर धारित करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए दूरस्थ वोटिंग ("**रिमोट ई-वोटिंग**") सहित वोटिंग का तरीका सूचना में दिया गया है। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कर सकेंगे।

ई-मेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने की रीति :

क) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य : लिंक इनटाइम के साथ ई-मेल पता पंजीकृत करके। उनकी वेबसाइट **www.linkintime.co.in** पर लिंक **Investor Services** टैब को क्लिक करके **E-mail Registration** शीर्षक चुनें और उसमें निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। सदस्यों से नाम, डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी/पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी जैसे विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया जायेगा। किसी भी जिज्ञासा के मामले में, सदस्य लिंक इनटाइम को **rmt.helpdesk@linkintime.co.in** पर ई-मेल भेज सकते हैं।

ख) इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी से सभी संचार प्राप्त करने के लिए डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके संबंधित डीपी के साथ डीमैट धारिता के संबंध में अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करके।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस और विषेश रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते डेल्हीवेरी लिमिटेड
ह./-
सुनील कुमार बंसल
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथि : 01 सितम्बर, 2022
स्थान : गुरुग्राम

पंजीकृत कार्यालयः एन24-एन34, एस24, एस34, एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स सेंटर-II, सामने गेट 6 कार्गो टर्मिनल, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 5, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122002, हरियाणा–122002
वेबसाइटः www.delhivery.com; **ई–मेलः** corporateaffairs@delhivery.com; **दूरभाषः** +91 124 6225602

फॉर्म-3
[विनियम-15(1)(ए)/16(3)]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, कोलकाता (डीआरटी 1)
9वां तल, जीवन सुधा भवन, 42सी, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-700071
मामला नं. ओए/5/2022

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (विधि) नियमों, 1993 के नियम 5 के उप नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन समन

ईएक्सएच नं.: 2159

भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
श्री साजेद खान

प्रति,
(1) **श्री साजेद खान**
डी/डब्ल्यू/एस/ओ- पुत्र स्वर्गीय हबीब अशरफ खान, निवासी 9, एकबालपुर लेन, खिदिरपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700023

समन

चूंकि, दिनांक 17.02.2022 को ओए/5/2022 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था।

चूंकि, यह माननीय न्यायाधीकरण द्वारा राशि 65,76,848.00 **रुपए** के ऋणों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल (ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत कथित आवेदन पर समन/नोटिस जारी करता है। (दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के तद्नुसार, प्रतिवादी को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता हैः-

(i) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कारण बताना होगा कि जिसके लिए राहत की प्रार्थना की गई है वह क्यों प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

(ii) मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट संपत्तियों तथा परिसंपत्तियों के अलावा संपत्तियों तथा परिसंपत्तियों का विवरण प्रदर्शित करना।

(iii) आपको मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत प्रदर्शित की गई प्रतिभूतित परिसंपत्तियों या ऐसी किसी अन्य परिसंपत्तियों तथा संपत्तियों के साथ लेन-देन और निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता है, साथ जुड़ी हुई संपत्तियों के लिए आवेदन की सुनवाई एवं निपटान लंबित है।

(iv) आप न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रदर्शित किसी परिसंपत्ति या किसी अन्य संपत्तियों, जिस पर प्रतिभूति ब्याज सृजित किया है, पर अपने व्यापार के सामान्य कोर्स को छोड़कर बिक्री, लीज़ या अन्यथा तरीके द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकोगे।

(v) आप व्यापार के सामान्य कोर्स में प्रतिभूति परिसंपत्तियां या अन्य परिसंपत्तियां तथा संपत्तियों की बिक्री द्वारा बिक्री प्रक्रिया से वसूली और ऐसी परिसंपत्तियों के ऊपर प्रतिभूति ब्याज को धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ रखे गए खाते में ऐसी बिक्री प्रक्रिया की राशि को जमा करने के उत्तरदायी होंगे।

आपको आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई उस प्रति के साथ लिखित बयान को दाखिल करने तथा दिनांक 12.12.2022 **को पूर्वाह्न** 10.30 **बजे रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल होने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायाधिकरण की मुहर के अधीन 12.07.2022 को जारी किया गया।

हस्ता/-
प्रभारी रजिस्ट्रार
ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, कोलकाता
वित्त मंत्रालय

भारतीय साधारण बीमा निगम

आपत्काले रक्षिष्यामि
GIC Re

(भारत सरकार की कंपनी)
पंजीकृत कार्यालय: 'सुरक्षा', 170, जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020
टेलीः + 91-22-2286 7000 **फ़ैक्स:** + 91-22-2288 4010,
वेबसाइट: www.gicofindia.com, **ई-मेल:** investors.gic@gicofindia.com,
सीआईएन: L67200MH1972GOI016133, **आईआरडीएआई पंजी. सं.** 112

50 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

वार्षिक आम बैठक की सूचना:

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लागू एमसीए परिपत्रों और कंपनी अधिनियम तथा सेबी विनियम (सामूहिक रूप से सांविधिक प्रावधान के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्यों का लेन-देन करने के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम की **50 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, दिनांक 26 सितंबर 2022 दोपहर 3:00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी. एजीएम की कार्यवाही निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी.

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट :

एजीएम बैठक की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट **शुक्रवार, 2 सितंबर 2022** के ईमेल से उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) रजिस्ट्रार / ट्रांसफ़र एजेंट्स (आरटीए) के पास उपलब्ध हैं. उक्त दस्तावेज़ निगम की वेबसाइट www.gicofindia.com, स्टॉक एक्सचेंज (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) एवं ई-वोटिंग एजेंसी मेसर्स नेशनल सेक्युरिटीज़ डिपॉसिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वोटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, निगम ने मेसर्स नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की सेवाओं को दूरस्थ ई-मतदान सुविधा के प्रावधान के लिए निम्नवत् लागू किया है :

विवरण	एजीएम से पूर्व	एजीएम के दौरान
दूरस्थ ई-वोटिंग का आरंभ	**बुधवार, 21 सितंबर 2022 को सुबह 09:00 बजे से (भारतीय मानक समयानुसार)**	**सोमवार, 26 सितंबर 2022**
दूरस्थ ई-वोटिंग का समापन	**रविवार, 25 सितंबर 2022 को शाम 05:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)**	**सोमवार, 26 सितंबर 2022 (एजीएम समाप्त होने के 15 मिनट बाद)**
कट ऑफ डेट (वोट के लिए हकदार)	**सोमवार, 19 सितंबर 2022**	
एक्सेस के लिए वेबलिंक	https://www.evoting.nsdl.com	
ई-वोटिंग इवेंट नंबर	EVEN-121687	

टिप्पणियाँ:

1. केवल वही व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तारीख अर्थात **सोमवार, 19 सितंबर 2022** तक सदस्यों / लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज है, दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ वार्षिक आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा.
2. सदस्यों का मतदान अधिकार **19 सितंबर 2022** तक निगम की चुकता साम्य शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा.
3. ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है या कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की नोटिस भेजने के बाद लेकिन कट ऑफ़ तारीख से पहले यानि **19 सितंबर 2022** तक निगम का सदस्य बने हों, सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के लिए फोलियो नं./डीपी-आइडी क्लाइंट आइडी का उल्लेख करते हुए निगम को investors.gic@gicofindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं. ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करें.
4. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग से अपने वोट डाले हैं, वे भी वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन वे फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे.
5. जो सदस्य वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम के दौरान वोट करने के हकदार होंगे.
6. जो सदस्य वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में सांविधिक रजिस्टरों / दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक हैं, एजीएम की तारीख तक अपनी डीपी-आईडी और क्लाइंट आईडी या फोलियो का उल्लेख करते हुए इस संबंध में निगम को ईमेल आईडी cs.gic@gicofindia.com पर मेल डाल सकते हैं.
7. जो सदस्य एजीएम के दौरान सवाल पूछना चाहते हैं, उन्हें **सोमवार 19 सितंबर 2022 (09:00 बजे भारतीय मानक समय) और बुधवार, 21 सितंबर 2022 (05:00 बजे भारतीय मानक समय)** के बीच gicagm.speakers@gicofindia.com पर अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अनुरोध भेजकर खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत करना होगा. केवल उन्हीं सदस्यों को, जिन्होंने वक्ता के रूप में पूर्व-पंजीकृत किया है, ई-एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी. निगम के पास ई-एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर बोलने वालों की संख्या को सीमित करने का अधिकार है.
8. किसी भी प्रकार की पूछताछ के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com पर शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज़) और एनएसडीएल के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं. सदस्य निम्नलिखित पर भी संपर्क कर सकते हैं:

टोल फ्री नं.: 1800-222-990 या 1800-22-44-30 या श्री अमित विशाल या सुश्री पल्लवी म्हात्रे से एनएसडीएल से ईमेल evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं.

यह सार्वजनिक सूचना निगम की वेबसाइट (www.gicofindia.com) पर भी उपलब्ध है.

कृते भारतीय साधारण बीमा निगम

हस्ताक्षरित/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

स्थान: **मुंबई**
दिनांक: **02.09.2022**

जनसत्ता

सामरिक उपलब्धि

स्वदेशी तकनीक से बने विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत के जलावतरण से भारत की सामरिक ताकत और आत्मविश्वास निस्संदेह काफी बढ़ गया है। करीब सोलह सौ सदस्यों वाले चालक दल के लिए तैयार किया गया यह युद्धपोत एक तरह से समुद्र में चलती-फिरती वायु और जलसेना छावनी की तरह काम करेगा। इस पर एक समय में करीब तीस हल्के लड़ाकू विमान और हेलिकाप्टर तैनात किए जा सकेंगे। इस तरह यह देश का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत है। हालांकि अमेरिका, चीन और रूस के पास इससे कुछ अधिक क्षमता वाले पोत हैं, पर विक्रांत के जलावतरण के बाद भारत अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस की कतार में खड़ा हो गया है। भारत के पास एक और विमानवाहक पोत सक्रिय है- विक्रमादित्य। यानी अब भारत के पास दो ऐसे युद्धपोत हो गए हैं। चीन के पास भी इतने ही पोत हैं। विक्रांत के संचालन से इसके जरिए मिग आदि लड़ाकू विमानों को समुद्र में उतारने और उड़ान भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। विक्रांत खुद एक युद्धक जलपोत है। इस तरह हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ गई है। स्वाभाविक ही विक्रांत के संचालन से खासकर पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ गई है। अभी तक हिंद महासागर में चीन का दबदबा बना हुआ था और अपनी सामरिक ताकत के बल पर वह भारत को धौंस देता रहता है। इससे उसका मनोबल कुछ कमजोर होगा।

विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इसमें देश की करीब पांच सौ छोटी-बड़ी कंपनियों ने सहयोग दिया। इसके पहले वाला विक्रांत युद्धपोत ब्रिटेन से मंगाया गया था। विक्रमादित्य रूस से खरीदा गया था। इस तरह विक्रांत की सफलता के बाद भारत का स्वदेशी सैन्य साजो-सामान के मामले में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प विक्रांत के जलावतरण से साकार होता दिख रहा है। भारत उन देशों में है, जो अपने सैन्य साजो-सामान पर काफी धन खर्च करता है। इसलिए कई देश उससे सैन्य उपकरणों की खरीद आदि के लिए लालायित रहते हैं और इसके मद्देनजर अपने अंतरराष्ट्रीय रिश्तों और रणनीतियों में बदलाव भी करते रहते हैं। कई बार इसी आधार पर वे भारत पर दबाव बनाने का प्रयास करते देखे जाते हैं। दरअसल, कई देशों की अर्थव्यवस्था सैन्य साजो-सामान के कारोबार पर निर्भर है। वे बिचौलियों को मोटा कमीशन, घूस आदि देकर लड़ाकू विमान, हेलिकाप्टर, पनडुब्बी, हथियार आदि खरीदने का सौदा कराते रहते हैं। अगर भारत इस मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाता है, तो न सिर्फ इन अड़चनों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि वह खुद एक सैन्य साजो-सामान के बाजार में खड़ा हो सकता है। इसका रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इसलिए भी हथियार बनाने वाले देशों को विक्रांत का जलावतरण खटक रहा होगा।

सबसे बड़ी बात कि विक्रांत की हिंद महासागर में मौजूदगी से चीन का एकाधिकार समाप्त होगा और वह भारत को जब-तब आंखें दिखाने से बचेगा। अभी भारत को हिंद महासागर में सबसे अधिक चुनौती चीन की तरफ से ही मिलती रही है। पाकिस्तान भी उसी की शह पर भारत को उकसाने का प्रयास किया करता था। अब वह ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस युद्धपोत में पानी के भीतर से आसमान में मार करने वाले अत्याधुनिक हथियार लगे हुए हैं। दुश्मन पनडुब्बियों की टोह लेने में भी आसानी हो गई है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि विक्रांत के आने से हिंद प्रशांत और हिंद महासागर में शांति का वातावरण बनेगा।

टकराव का हासिल

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच औपचारिक बैठकों तक में स्थिति जैसी होती जा रही है, उससे सवाल यह पैदा हो रहा है कि इससे राजधानी और यहां के लोगों का क्या भला हो रहा है! शुक्रवार को दोनों के बीच होने वाली साप्ताहिक बैठक टलने की वजह यह बताई गई कि चूंकि अरविंद केजरीवाल गुजरात के दो दिनों के दौरे पर हैं, इसलिए उपराज्यपाल के साथ होने वाली बैठक में वे शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन लगातार तीसरी बार हर सप्ताह होने वाली बैठक में शामिल नहीं होना यह बताने के लिए काफी है कि दोनों के बीच कई मुद्दों पर हो रहे टकराव की वजह से पैदा होने वाला तनाव अब किस रूप में दिखने लगा है। सवाल है कि अगर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली बैठक का मकसद राजधानी दिल्ली में सरकार चलाना और शासन का सहज रूप से कामकाज सुनिश्चित किया जाना है तो इसमें निजी आग्रहों की जगह क्यों होनी चाहिए। वहीं, अगर बैठकें नहीं हो पाने की वजह कोई आग्रह, तनाव या टकराव नहीं है तो क्या इसे शासन चलाने के लिए जरूरी कामों की प्राथमिकता सूची में कम महत्त्व का माना जा रहा है?

दरअसल, पिछले काफी समय से उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जिस स्तर की खींचतान चल रही है, उसमें यह साफ दिख सकता है कि इसकी वजह केवल तकनीकी बाध्यताएं नहीं होंगी। दिल्ली में 'आप' की सरकार की ओर से कई पार्टी के नेता यहां के विकास को बाधित करने के आरोपों के साथ उपराज्यपाल को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। दूसरी ओर, उपराज्यपाल की ओर से कुछ तकनीकी आधार के चलते सरकारी कामकाज से संबंधित फाइलों पर सवाल उठाया जा रहा है। मसलन, उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई सैंतालीस फाइलों को इसलिए वापस भेज दिया कि उन पर संवैधानिक मानदंडों के मुताबिक मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं थे। इस बीच, दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े विवाद ने कई स्तर पर जो संदेह खड़े किए हैं, वह अब एक सार्वजनिक बहस का विषय हो चुका है। फिर उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से यहां के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के लिए अतिरिक्त कमरे बनाने से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में भी रिपोर्ट तलब की। जाहिर है, इन मसलों पर दिल्ली में 'आप' एक तरह से घिरी हुई है।

यह बेवजह नहीं है कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी उपराज्यपाल पर चौदह सौ करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए दावा किया गया कि जब वे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के पद पर थे, उस दौरान यह घोटाला हुआ था। जाहिर है, दोनों पक्षों के बीच टकराव ने जो शक्ल अख्तियार कर लिया है, उसमें मामला अब केवल आपसी तनाव तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर अब राज्य के सामान्य कामकाज पर भी पड़ने लगा है। पिछले कई हफ्तों से जिस तरह उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बैठकें रद्द होने का जो क्रम चल रहा है, उसका हासिल आखिर क्या होने वाला है? दिल्ली को देश के सभी राज्यों से अलग और विशेष चेहरा देने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए यहां के विकास और लोगों के हित प्राथमिक हैं या आपसी खींचतान के बीच पलता कोई अहं? वहीं, अगर उपराज्यपाल के सामने भी अगर कोई बड़ी बाधा नहीं है तो उन्हें भी टकराव या तनाव के बजाय जनहित में दोनों पक्षों के बीच सौहार्द के हालात बनाते हुए अपनी गरिमा को कायम रखने की जरूरत है, ताकि दिल्ली और यहां के लोगों के लिए एक बेहतर शासन और विकास सुनिश्चित किया जा सके।

कल्पमेधा

रहस्य सत्य का मित्र नहीं है। किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान देकर विनम्र बनने की आवश्यकता नहीं है।
- वोल्तेयर

बढ़ते हाथ, घटते काम

सरोज कुमार

इतने बड़े घरेलू बाजार में मांग होती, तो निर्यात घटने के बाद भी विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, और रोजगार की परिस्थिति इतनी जटिल नहीं होती। मगर गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम आबादी के पास मांग करने की शक्ति नहीं रह गई है। इसका खमियाजा रोजगार बाजार, और अंत में अर्थव्यवस्था को भुगतना है।

बाजार जब रोजगार पैदा करना बंद कर दे तो समझिए अर्थव्यवस्था नीतिगत बीमारी की शिकार हो गई है, जिसका इलाज मुश्किल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। चिंता की बात यह है कि कुशल हाथ बेकार हैं, फिर भी श्रम बाजार सिकुड़ रहा है। भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बेशक दुनिया के देश कमोबेश कठिनाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारत की कठिनाई अलग तरह की है। विशाल उपभोक्ता बाजार और उत्पादन की क्षमता होने के बावजूद यहां मांग और आपूर्ति का संकट है। बेरोजगारी की लंबी खिंचती परिस्थिति के बीच मांग में अतिरिक्त गिरावट की आशंका है। मांग खर्च पर निर्भर होती है और खर्च कमाई पर। कमाई की क्या स्थिति है, आंकड़े नहीं, जेब टटोल कर देख लीजिए।

मांग की एक नई खिड़की निर्यात में वृद्धि के साथ खुली थी, और उसके साथ ही रोजगार बाजार के पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी थी। मगर भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दुनिया में मंदी की आहट के साथ यह खिड़की भी बंद होती दिख रही है। निर्यात घटेगा तो जाहिर है विनिर्माण का इंजन सुस्त पड़ जाएगा। रोजगार की पैदावार रुक जाएगी। भारतीय निर्यात में उछाल से उत्साहित कारपोरेट जगत ने 2021-22 में 791 परियोजनाओं के लिए 1,94,548 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की थी, जो 2020-21 की 576 परियोजनाओं के लिए 1,16,603 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा से काफी अधिक है। अगर यह सारा निवेश बाजार में उतरता तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बनते। मगर जब मांग की ही संभावना धूमिल हो चली है, तो ऐसी स्थिति में भला कौन निवेशक अपनी पूंजी गड्ढे में फेंकना चाहेगा?

महामारी की रफ्तार थमने के बाद दुनिया के बाजार खुले तो मांग में भी तेजी आई। भारत ने 2022 में अब तक के रिकार्ड 421.89 अरब डालर का निर्यात किया। लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध ने परिस्थिति को पलट दिया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आहट के कारण मांग घटने लगी है। इसका असर भारत के निर्यात पर पड़ा है। जुलाई 2022 में भारत का निर्यात गिर कर 35.24 अरब डालर हो गया, जो जून में 35.51 डालर था।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च ने अपने एक अध्ययन रपट में कहा है कि निर्यात में वृद्धि के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 2022 में जो तेजी आई थी, निर्यात में गिरावट के कारण वह 2023 में नहीं रहने वाली है। एजेंसी के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की चिंता और चीन में कोविड नियंत्रण के कड़े उपायों के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित हुआ है। रपट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 के दौरान भारत का वार्षिक औसत निर्यात 297.02 अरब डालर रहा था, जो वित्त वर्ष 2019 में बढ़ कर 330.08 अरब डालर हो गया। और 2021-22 में यह रिकार्ड 421.89 अरब डालर पर पहुंच गया। निर्यात में यह वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के कारण हुई। यानी विनिर्मित उत्पादों का निर्यात बढ़ने से औद्योगिक इकाइयों ने अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन किया, और इसके कारण 2022 में नौकरियों की उम्मीद भी वापस लौटी। लेकिन मंदी के आसन्न संकट ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है।

भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के दो सबसे बड़े ग्राहक अमेरिका और यूरोप के लिए निर्यात की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआइएस) के आंकड़े बताते हैं कि यूरोप के लिए भारतीय निर्यात की वृद्धि दर जून 2022 में घट कर उनतालीस फीसद रह गई, जो अप्रैल 2022 में इकसठ फीसद और मई 2022 में चालीस फीसद थी। इसी तरह अमेरिका के लिए भारतीय निर्यात की वृद्धि दर जून में घट कर उनतीस फीसद रह गई, जो मई में बत्तीस और अप्रैल में इकतीस फीसद थी। वित्त वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में भारत ने यूरोप को 19.3 अरब डालर, और अमेरिका को 21.7 अरब डालर मूल्य की वस्तुओं-सेवाओं का निर्यात किया। भारतीय सामान के चौथे सबसे बड़े ग्राहक चीन के लिए निर्यात जून तिमाई में इकतीस फीसद घट कर 4.7 अरब डालर रह गया। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका और यूरोप की सम्मिलित हिस्सेदारी 2022 में

तैंतीस फीसद थी, जबकि चीन की हिस्सेदारी पांच फीसद। यानी भारतीय निर्यात का अड़तीस फीसद हिस्सा संकट में है। निर्यात के इतने बड़े हिस्से के संकटग्रस्त होने से घरेलू उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा, और इसका रोजगार पर क्या असर होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है।

इस साल गेहूं का उत्पादन दस से तीस फीसद घट गया। अब असमान बारिश के कारण धान का उत्पादन भी आठ फीसद कम होने का अनुमान है। यानी जिस कृषि क्षेत्र ने महामारी के दौरान रोजगार बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों को सहारा दिया था, वहां से भी घरेलू मांग में किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। इतने बड़े घरेलू बाजार में मांग होती, तो निर्यात घटने के बाद भी विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, और रोजगार की परिस्थिति इतनी जटिल नहीं होती। मगर गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम आबादी के पास मांग करने की शक्ति नहीं रह गई है। इसका खमियाजा रोजगार बाजार, और अंत में अर्थव्यवस्था को भुगतना है।

सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआइई) के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय रोजगार बाजार इस समय एक विचित्र स्थिति में पहुंच चुका है। यह बूढ़ी और कम पढ़ी-लिखी श्रमशक्ति की एक बस्ती बन चुका है। यहां कामकाजी उम्र के पढ़े-लिखे युवाओं के लिए काम नहीं है। कामकाजी उम्र (15-24 वर्ष) का हो जाने के बाद भी युवा आबादी विद्यार्थी जीवन जीने को मजबूर हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां कामकाजी उम्र के लगभग पंद्रह फीसद लोग विद्यार्थी थे, वहीं 2019-20 में इस उम्र के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ कर अठारह फीसद हो गई। 2020-21 में इक्कीस फीसद और 2021-22 में तेईस फीसद हो गई। वित्त वर्ष 2016-17 और 2021-22 के बीच देश में कामकाजी आबादी 12.10 करोड़ बढ़ गई, जबकि इसी अवधि में श्रमशक्ति एक करोड़ घट गई।

वित्त वर्ष 2016-17 में देश में रोजगार में लगी कुल श्रमशक्ति का एक-चौथाई हिस्सा तीस साल तक की उम्र के लोगों का था। जो 2019-20 में घट कर इक्कीस फीसद और 2021-22 में अठारह फीसद रह गया। अर्थव्यवस्था के लिए यह एक खतरनाक संकेत है। किसी देश की कामकाजी युवा आबादी वहां की बड़ी पूंजी मानी जाती है। जब देश अपनी उपलब्ध पूंजी का ही उपयोग न कर पाए तो वह किस घाट लगेगा, कह पाना कठिन है।

भारतीय श्रम बाजार में पढ़े-लिखे लोगों के लिए भी जगह नहीं रह गई है। वित्त वर्ष 2018-19 में जहां स्नातक और परास्नातक श्रमिकों की हिस्सेदारी 13.4 फीसद थी, वहीं 2021-22 में यह घटकर 12.2 फीसद रह गई। भारतीय श्रमशक्ति का बड़ा हिस्सा छठी से बारहवीं पास लोगों का है। वित्त वर्ष 2016-17 में दसवीं, बारहवीं पास श्रमिकों का हिस्सा अठाईस फीसद था, जो 2021-22 में बढ़ कर अड़तीस फीसद हो गया। वित्त वर्ष 2016-17 में श्रमशक्ति में ऐसे श्रमिकों की हिस्सेदारी अठारह फीसद थी, जो 2021-22 में बढ़ कर उनतीस फीसद हो गई।

बाजार में मांग नहीं, श्रम बाजार में रोजगार नहीं, और निजी निवेशक तैयार नहीं। बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। फिर तो भविष्य बेरोजगारी और बदहाली का ही है।

जड़ता की अंधी गलियां

भावना मासीवाल

दुनिया मेरे आगे

हमारे देश की आजादी के पचहत्तर वर्ष पूरे हो गए हैं और इसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया भी गया। इस महोत्सव के मूल में ब्रिटिश हुकूमत से भारत की आजादी है। हम बाहरी ताकतों से देश के आजाद होने का उत्सव हर वर्ष मनाते ही हैं, लेकिन यह वर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक तरफ जब पूरा देश आजादी के इस महापर्व के उल्लास और उमंग में था तो दूसरी तरफ राजस्थान के एक स्कूल में हुई घटना हमें देश के भीतर की अराजक व संकीर्ण मानसिकता से भरी ताकतों से घिरे होने का अहसास कराती हैं। बाहरी ताकतों से तो हमें आजादी मिल गई और हम देशवासी फिर से बाहरी ताकतों से एकजुट होकर लड़ सकते हैं, अलग-अलग अपेक्षाएं और उनकी सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन जो ताकतें देश के भीतर विराजमान हैं, उनसे लड़ना और उनकी सीमाओं का निर्धारण करना सरल नहीं है।

दरअसल, हम आजाद देश के नागरिक जरूर हैं, मगर भीतर से परंपरा के नाम पर कई विकृत रूढ़ियों से बंधे हैं। ये रूढ़ियां हमारे विचार व व्यवहार में इतनी अधिक संकीर्ण है कि समाज को भीतर से खोखला और अपंग बना रही हैं। यह अपंगता व्यक्ति के विचार और व्यवहार में देखी जा सकती है। हम चाह कर भी इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि कहीं राजस्थान में मासूम बच्चे द्वारा पानी पीने के मटके को छू देने भर के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोने की खबर आती है तो कहीं स्त्री होने के कारण यौन शोषण के त्रासद अपराध के दौर से गुजरना पड़ता है और जीवन भर अपने ही खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ अकेले लड़ना पड़ता है। हमारे आसपास ऐसी बहुत-सी घटनाएं होती रहती हैं जो हमें खुद से ही सवाल करने पर मजबूर करती है। लेकिन सच यह है कि हम उन सवालों के जवाब न पाकर व्यवस्था के प्रति आक्रोश जाहिर करने लगते हैं। यह आक्रोश कभी न्याय का मजबूत पक्ष बनता है तो कभी अन्याय का।

यह हमारे समय की विडंबना ही कही जाएगी कि एक तरफ हम देश को वैश्विक फलक पर मजबूत प्रतिनिधि के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, हम एक राष्ट्र, प्रेम और सौहार्द का गीत गाते हैं, मगर वहीं हमारे ही बीच के कुछ लोग उस राष्ट्रभाव और एकता के बंधन को अपनी संकीर्ण, जड़ और हिंसक प्रवृति के कारण खंडित करते देखे जाते हैं। फिर वह जाति और जेंडर की संकीर्ण मानसिकता ही क्यों न हो। जबकि इस कसौटी पर नाकाम समाज और देश अपने न्यायपूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता। यों भी किसी देश की उन्नति उसके नागरिकों के आपसी सहयोग व सौहार्द से होती है। जब आम नागरिक ही सामाजिक रूढ़ियों, जातिगत भेदभाव की बंदिशों से घिरा होगा तो हम किस राष्ट्र का विकास करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा भी था कि 'कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता, जब तक उसके लोगों की सोच या उनका काम संकीर्ण रहेगा'। यह एक देश और समाज के बनने के लिए एक शर्त के तौर पर देखा जाना चाहिए।

शिक्षा व्यक्ति को मनुष्य बनाती है, उसमें आत्मसम्मान, प्रेम, आजादी, सौहार्द, भाईचारे, समानता का भाव जगाती है। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में आपसी सौहार्द से अधिक जातिगत तो कभी सामाजिक लिंग यानी जेंडर के मसले पर तो कभी क्षेत्रगत वैमनस्य का भाव देखने को मिलता है। यह भाव कभी श्रेष्ठता के झूठे बोध की ग्रंथि से तो कभी हीनता बोध की ग्रंथि से ग्रसित मिलता है। दोनों ही स्थितियों में यह समाज को खोखला और नई पीढ़ी को वैमनस्य के भाव से भर रहा है। यह वैमनस्य का भाव किताबी शिक्षा से अधिक व्यावहारिक शिक्षा और ज्ञान से दूर किया जा सकता है, लेकिन इसे अपने हाल में या यथास्थिति में छोड़ देने के नतीजा यह होगा कि राजस्थान जैसी कितनी ही घटनाएं घटित होती रहेंगी और एक व्यक्ति की संकीर्ण मानसिकता पूरे समाज और राष्ट्र को कठघरे में खड़ा करती रहेगी।

हम इस सच से भी वाकिफ हैं कि हमारे समाज की इस जड़ मानसिकता को खाद पानी देने का काम राजनीति ने ही किया है। दरअसल, राजनीति इसी व्यवस्था को हथियार बनाकर अपना वोट बैंक तैयार करती है। यही वोट बैंक फिर समाज में राजनीति के समीकरण तैयार करता है और जड़ संकीर्ण मानसिकता को पैदा करता है। एक ओर समाज में जाति व्यवस्था के टूटने की बात की जाती है तो दूसरी ओर जाति के भीतर उप-जातियां अधिक मजबूत बनकर उभर रही हैं। यह हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का ही हिस्सा है कि हम समाज और जातिगत व्यवस्था को बदलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर समाज बदलता है तो वर्चस्वशाली जातियों की जातिगत राजनीति भी टूटने लगेगी और जड़ मानसिकताएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी। लेकिन यह एक आम आदमी का दिवास्वप्न ही है, क्योंकि आज भी राजनीति में वर्चस्वशाली समूह अपनी सुविधा के मुताबिक मुद्दे उभरने देते हैं और उसके हल की खोज करते हैं।

कथनी-करनी

'अण्णा का आईना' (संपादकीय, 1 सितंबर) पढ़ा। इस विषय में यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल के गुरु अण्णा हजारे हैं। एक समय प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने के लिए जब अण्णा हजारे ने अपना आंदोलन किया था, तब अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन में शामिल हुए थे और आंदोलन का संचालन भी किया था। तब आंदोलन के समय ही केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गठन करने की भी घोषणा की थी। बाद में इसी पार्टी ने दिल्ली राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ कर जीता और फिर सरकार भी बनाई थी। वहीं केजरीवाल जब सच्चाई एवं ईमानदारी की कसमें खाने के बाद भी आज जब नैतिकता भूल बैठे हैं तो अण्णा हजारे उनसे नाराज हैं।

कारण स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जब उनके साथ थे, तब अण्णा हजारे उनकी ईमानदारी से काफी प्रभावित हुए थे, पर आज के समय में अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति से अण्णा हजारे काफी नाराज है। यही कारण है उन्होंने एक चिट्ठी भी केजरीवाल को लिखी, जिसमें उन्होंने सरकार की आबकारी नीति की आलोचना की और कहा कि आपकी पार्टी आजकल गलत नीति पर चल रही है... सरकार का शराब को बढ़ावा देना और रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना, दोनों ही एक तरह से गलत काम है। इनसे आम आदमी पंगु एवं खोखला हो रहा है।

हम तो यही कहेंगे कि जब आज के समय अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े नेता हैं तो उन्हें अपनी ख्याति और साख का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अण्णा हजारे, जो उनके राजनीतिक गुरु भी हैं, की बात को ध्यान रखकर अपनी छवि पर लगते दाग को धोने का अवश्य प्रयास करना चाहिए।

- मनमोहन राजावत राज, शाजापुर, मप्र

किसका विकास

एक सर्वे के अनुसार, भारत में आत्महत्या करने वालों में हर चौथा व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर है। इस खबर को पढ़ने के बाद हर संवेदनशील भारतीय का मन व्याकुल होना स्वाभाविक है, पर विचार और विमर्श का विषय है कि अन्य तीन हिस्से कौन हैं। क्या देश के अन्य आत्महत्या करने वालों के विषय में चिंता और चिंतन नहीं होना चाहिए? आखिर कोई भी इंसान आत्महत्या क्यों करे?

एक अन्य खबर पुर्तगाल से आई जहां इलाज में देरी के कारण एक गर्भवती महिला की मौत के बाद विभाग के मंत्री ने पदत्याग कर दिया। कहने का आशय यह कि असल वजह है जिम्मेदारी से भागना। अगर हमारे देश में भी जवाबदेही तय हो और नैतिक आधार को सर्वोपरि मानकर फैसले लिए जाएं तो शायद देश के किसी नागरिक को आत्महत्या करने की आवश्यकता ही न पड़े। हर जान कीमती है, रमेश हो या रियाज, आशा हो या अफसा, हर वर्ग जरूरी है दिहाड़ी मजदूर हो या किसान। व्यवस्था की भेंट कोई भी चढ़ता है तो ये निश्चित ही चिंता का विषय है।

- मनोज, मेरठ, उप्र

वक्त का तकाजा

आज के समय हर क्षेत्र में तेजी से खपत बढ़ रही है। मोबाइल ऐप ने इस काम को और भी आसान बना दिया है। चाहे खाने-पीने की चीज हो या कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण, आजकल सब कुछ घर बैठे ही उपलब्ध कराया जा सकता है। दवाइयों को घर तक उपलब्ध कराने के लिए भी ऐसे कई ऐप हैं जो वृद्ध एवं असहाय लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हुए हैं। आज से दस साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि ई-कामर्स इतनी बड़ी क्रांति लेकर आएगा। लेकिन इस क्रांति का एक चिंताजनक पहलू जरूरत से ज्यादा बढ़ती खपत भी है।

लोगों की बढ़ती आय और ई-कामर्स की आसान दुनिया ने लोगों को खपत के मामले में लापरवाह बना दिया है और उन्हें अपने द्वारा मंगाई गई वस्तु भी जल्द से जल्द चाहिए।

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

कई लोग चाहते हैं कि उन्हें उनका सामान दो-तीन घंटे से लेकर दिन के अंत तक मिल जाए। ऐसे में ई-कामर्स कंपनिया अपने वितरण प्रबंधकों पर जल्द से जल्द वितरण करने का दबाव बनाती हैं। हाल ही में जोमैटो द्वारा दस मिनट में डिलीवरी करने की घोषणा इस बात का प्रमाण है। उल्लेखनीय है कि ऐसे में वितरण कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के लिए बिना अपनी परवाह किए अपने काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में वे किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। अन्य कई तरह के नुकसान भी हो सकतेहैं।

इसलिए हमें अपनी जरूरत से ज्यादा हो रही खपत पर अंकुश लगाने की जरूरत है। वितरण कर्मचारी 'गिग वर्कर्स' की श्रेणी में आते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए कोई बीमा या अन्य सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में भारत सरकार को जल्द से जल्द इसका संज्ञान लेना होगा। आज यह एक विकल्प ही नहीं बल्कि समय की मांग है।

- विवेक चौबे, हावड़ा

सियासी आंकड़े

हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा अठारह ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में समाहित करने संबंधी अधिसूचना को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने सरकार के कामकाज पर सख्त टिप्पणी करते हुए संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश की अठारह ऐसी जातियां हैं, जिन पर हमेशा राजनीतिक दलों की निगाह टिकी होती हैं। इन जातियों को 2005 में मुलायम सिंह यादव ने, 2016 में अखिलेश यादव और 2019 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ओबीसी वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने संबंधित अधिसूचना जारी की थी।

दरअसल यह एक राजनीतिक कलाबाजी अलावा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की इन अठारह जातियों में निषाद केवट मल्लाह, राजभर, भर बाथम, नोनिया जातियों की आबादी कुल मिलाकर बारह फीसद है, जिनको सभी राजनीतिक अपने पाले में करना चाहते हैं। इस प्रकरण में सिर्फ बसपा का स्पष्ट मत रहा है कि अगर बिना आरक्षण बढ़ाए बारह आबादी को ओबीसी से अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया जाता है तो यह न्यायसंगत नहीं है। यह अनुसूचित जाति वर्ग के हितों पर कुठाराघात होगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि आरक्षण के बावजूद सार्वजनिक महकमों से लेकर लगभग हर स्तर पर अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी आज भी न्यायसंगत स्तर तक नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में किसी तरह मिल सके उनके अधिकारों में ही कटौती की जाने लगेगी या उनका हिस्सा कम किया जाने लगेगा तो इसे कैसे देखा जाएगा?

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से रुखसत होने के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी दो प्रतिद्वंद्वी चेहरे आमने-सामने आए। कांग्रेस नेतृत्व पर आरोपों की झड़ी लगाने वाले आजाद के घर उनसे मिलने के लिए अन्य असंतुष्ट नेताओं के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे थे। इसके बाद कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि नेताओं के इस कदम ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रमित और निराश किया है। कुमारी शैलजा ने सवाल किया कि जब एक शख्स ने पार्टी छोड़ दी है तो उनसे मिलने जाने का क्या औचित्य है।

कांग्रेस में पिछले दो दशक में संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए हैं। भारतीय राजनीति में जब कोई दल लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो संगठनात्मक स्तर पर लोकतांत्रिक कवायद से बेपरवाह हो जाता है। आलाकमान का वचन ही शासन होता है। कभी शीर्ष के बल पर शीर्ष में रखे गए नेता जितनी तेजी से कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगा कर पार्टी को अलविदा कह रहे हैं उतनी तेजी से तो पार्टी में सुधार संभव नहीं दिखता। इन नेताओं ने 2014 से पहले लोकतांत्रिक कांग्रेस की मांग नहीं की थी क्योंकि इन्हें सत्ता में अहम भागीदारी मिली थी तो संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी शायद विपक्षी दलों का काम समझ लिया गया था। आज जब कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव का एलान हो गया है तो देखना होगा कि चिट्ठी-क्रांति करने वाला समूह चुनाव में भाग लेता है या चुनावी प्रक्रिया खट्टी है कह कर मुंह फेर लेता है। कल तक दरबारी का बिल्ला लगा रखे नेताओं के बागी बोल पर बेबाक बोल।

बेबाक बोल

भाग दरबारी

मुकेश भारद्वाज

गुल भी मानिंद-ए-खार हैं अब तो
नंग-ए-फस्ल-ए-बहार हैं अब तो
- नामी नादरी

कांग्रेस के लिए यह समय राजनीतिक विपन्नता का है। राजनीतिक शक्ति के संसाधन में वह अर्श से फर्श पर पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है कि यह समय पार्टी के उन लोगों के लिए बहुत कष्टकारी होगा जिन्होंने लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगा है। अभी कांग्रेस महज दो जगहों पर सत्ता में है। पार्टी को अपने नेताओं के पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है सिवाय संघर्ष के लिए उत्साहित करने के। लेकिन, संघर्ष शब्द आदर्श रूप से जितना आकर्षक लगता है, व्यावहारिक रूप से उतना ही मुश्किल।

केंद्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद जितनी जल्दी जी-23 का जन्म हुआ वह उतना भी आश्चर्यजनक नहीं था। लंबे समय से जनता से दूर नेताओं के लिए सबसे आसान काम था, चिट्ठी लिख कर पार्टी आलाकमान से अपनी नाराजगी जताना। दूसरी ओर, सबसे मुश्किल काम था, जनता के बीच जाकर उनकी नाराजगी दूर करना। चिट्ठी लिखी गई, मीडिया को दी गई और बहुचर्चित हुई। कांग्रेस को उपदेशों की झड़ी के साथ पार्टी छोड़ने वालों की लड़ी लग गई। जो कल तक खुद 'राग दरबारी' सप्तम सुर में गा रहे थे, आज वे कह रहे हैं कि कांग्रेस सुरक्षाकर्मियों (इशारा शायद केबी बायजू की ओर था जो राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा के पूर्व सदस्य हैं) और चपरासियों के हवाले है। जरा सोचिए, दरबार की सुरक्षित कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों के लिए सुरक्षाकर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए कितनी घृणा है। आज गुलाम नबी आजाद उस खेमे के मुरीद हो रहे हैं जिसने राजनीति में इसी कथित सामंती संभ्रांत मानसिकता को तोड़ा है। आजाद की सामंती सुर की भाषा ही उनकी अचकन पर लगा उनकी पहचान बताने वाला बिल्ला उचक-उचक कर दिखा रही है।

इसके पहले अपनी राज्यसभा की सदस्यता खत्म होते ही कपिल सिब्बल के अंदर भी बगावत की क्रांति आई और वे कांग्रेस को छोड़ कर समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा सांसद बन गए। अभी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती का मैदान है। वहां चुनाव आने वाले हैं और पार्टी को बहुत मेहनत करनी है। जाहिर सी बात है कि हिमाचल में कांग्रेस विपक्ष में है और वहां आम आदमी पार्टी का उभार तेजी से हो रहा है तो कांग्रेस को मुकाबले में रहने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब मेहनत करने से अच्छा है कि किसी भी तरह की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ो। आनंद शर्मा ने हिमाचल में चुनौतियों का हिमालय देख आरोप और उपदेश का आसान रास्ता चुना।

चुनावों में लगातार मिल रही पार्टी की हार के बाद मनीष तिवारी से लेकर आनंद शर्मा तक पार्टी के संगठनात्मक ढांचे से नाराज हैं। पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिख कर अपनी नाराजगी दिखाई। अब इनकी नाराजगी दूर करने का मौका आ गया है। कांग्रेस ने संगठनात्मक ढांचे में आम चुनाव का एलान कर दिया है। पार्टी का संदेश है कि लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाए, चाहे वह राहुल गांधी हों या कोई और। अब, वे सभी नेता जिन्हें लगता है कि राहुल इस जिम्मेदारी के योग्य नहीं हैं उन्हें अध्यक्ष-पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी के संविधान के मुताबिक पार्टी का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ सकता है। अध्यक्ष पद के लिए इंदिरा गांधी तक को चुनौती दी भी जा चुकी है। सीताराम केसरी को शरद पवार और राजेश पायलट ने चुनौती दी थी। सोनिया गांधी को जितेंद्र प्रसाद ने चुनौती दी थी।

डूबती हुई नाव से सबसे पहले वही भागते हैं जिनमें जहाज खेने का जज्बा न बचा हो। अभी दरबारी पुराण छेड़ कर सवाल उठाने वाले लोग वहीं हैं जो नब्बे के दशक में मनमोहन सिंह के समय में कांग्रेस में उभरे। इन नेताओं का संबंध कभी भी जमीनी राजनीति से नहीं रहा है। इन सबने कांग्रेस की बनी-बनाई जमीन पर अपनी सुविधाजनक राजनीति की आलीशान इमारत बनाई। राहुल गांधी की अयोग्यता की दलील देने वाले सभी हुनरमंद नेता हैं जो कांग्रेस के आधार पर ही स्थापित हुए।

अब जब बना-बनाया आधार खिसक गया है तो इनके पास क्षमता नहीं है कि अपना आधार बनाने के लिए संघर्ष करें। कांग्रेस में लंबे समय से तो कोई आधार बनाने के लिए गया ही नहीं। आधार बनाने का सारा काम ऊपर से ही हुआ। ये सभी ऊपर से ही डाले गए नेतृत्व थे। नेतृत्व ने ही इन्हें उठा कर मंत्रिमंडल में लिया। ये हमेशा शीर्ष पर शीर्ष की बदौलत ही रहे। आज जब इनके पांवों ने जमीन मांगी तो हवा में लटकने का सारा दोष भी शीर्ष पर ही डाल रहे।

राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि कांग्रेस की कमान उन्हें तब मिली जब यह चौतरफा संकटों से घिर चुकी थी। अब उनके पास तो ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितिन प्रसाद की तरह भाजपा में चले जाने की सुविधा है नहीं। विरासती नेता का आरोप उन्हें झेलना है तो इस विरासत को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ उन्हीं की मानी जा रही है। दूर से तो राहुल गांधी की कोशिश ऐसी टीम खड़ी करने की दिख रही है जो जमीन से जुड़ी हुई संघर्षशील हो। राहुल संगठन का ढांचा भी दुरुस्त करने की कवायद में दिख रहे हैं। इन सब में सिर्फ आसमानी दलील वाले बेजमीनी नेता कहीं से भी योग्य नहीं ठहरते हैं। यहीं से विरोधाभास शुरू होता है। हर चुनावी हार के बाद नेताओं की पार्टी छोड़ने की सुविधाजनक दलील शुरू हो जाती है।

चाहे वे अशोक गहलोत हों या दिग्विजय सिंह, इन नेताओं में इस तरह का संकट नहीं दिखता है। सत्ता से दूर रहने की हताशा तो स्वाभाविक है लेकिन इनके पास अपनी बनाई जमीन है तो वापसी की उम्मीद भी रहती है। संकट में वे ज्यादा दिखे जो कांग्रेस की बनी-बनाई जमीन पर स्थापित किए गए। जो कभी सत्ता के गलियारे में आसमान से टपके और अब सत्ता के लिए कहां जाएं की सोच पर अटके हैं।

भाजपा लगातार दूसरी पारी खेल रही है और आगे भी उसका भविष्य उज्ज्वल ही दिख रहा है। चुनाव सुधार के नाम पर चुनावी चंदे का भी सीधा-सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। ये लोग वैसे शाही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की गरीबी के दिन नहीं देखे थे। ऐसी स्थिति में चाहे कपिल सिब्बल हों या गुलाम नबी आजाद, अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी करने के लिए पार्टी छोड़ना ही बेहतर समझ रहे हैं।

पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठा रहे नेता आगे नजीर तभी बनेंगे जब वे सांगठनिक चुनाव का हिस्सा बन कांग्रेस में सुधार को लेकर अपनी गंभीरता दिखाएं। अगर आपने इस मौके का फायदा नहीं उठाया और सिर्फ प्रक्रियागत दोष निकाला तो यही माना जाएगा कि आप कांग्रेस के बने रहने के खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि उसका खेल ही खराब कर देना चाहते हैं। जैसे कि सारे विपक्षी दल चुनाव से पहले ही ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। वहीं, दिल्ली व पंजाब में उनकी जीत हो जाती है तो फिर उन्हें विपक्ष में कोई खामी नजर नहीं आती है। यानी हार के पहले ही आरोपों का प्रहार करने का रास्ता आप बना लेना चाहते हैं।

कांग्रेस के बागी नेता संगठनात्मक चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं तो यही माना जाएगा कि आप में और विपक्ष में इतना ही फर्क है कि वे पार्टी के बाहर हैं और आप अंदर। अगर आपने चुनावों में हिस्सा लिया और 23 वोट ही हासिल कर लिए तो भी आप अपनी चिंताओं को वैधानिकता दे पाएंगे। नहीं तो यही माना जाएगा कि आप कोई नया रास्ता नहीं बनाना चाहते, सिर्फ पिछले दरवाजे से कुर्सी, बंगला ही सुरक्षित रखना चाहते हैं।

गहराया संकट

झारखंड में राजनीतिक अनिश्चितता शुक्रवार को तब और बढ़ गई जब राज्यपाल रमेश बैस रांची से दिल्ली चले गए। राजभवन के सूत्रों ने इसे गैर राजनीतिक यात्रा बताया पर माना यही जा रहा है कि

वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सियासी भविष्य पर फैसला करने से पहले केंद्र सरकार से मंत्रणा करने के मकसद से गए हैं। इससे पहले यूपीए के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात कर चुनाव आयोग की सिफारिश पर फैसला जल्द करने का आग्रह किया था। बैस ने एक तो यह बात मान ली थी कि चुनाव आयोग की सिफारिश उन्हें मिल चुकी है। दूसरे उन्होंने फैसला दो-तीन दिन में करने का भरोसा भी दे दिया था। यह बात अलग है कि राज्यपाल पर फैसला करने के लिए कानूनन समय-सीमा की कोई बाध्यता नही है। चुनाव आयोग ने माना है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए निजी लाभ के लिए फैसला किया था। इस नाते उनकी विधानसभा सदस्यता का जाना तो तय ही माना जा रहा है। दुविधा बस इसे लेकर है कि उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाता है या नहीं? बताते हैं कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल से ऐसी कोई सिफारिश नही की है। बहरहाल पहले चर्चा थी कि हेमंत विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। लेकिन अब उन्होंने दो मोर्चों पर रणनीति बनाई है। एक तो यूपीए के विधायकों को दल-बदल से बचाने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेजा है। दूसरे पांच सितंबर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें बहुमत दिखाने की उनकी योजना है। वैसे इस तरह का संकट मनमोहन सरकार के दौर में एनएसी का अध्यक्ष होने के कारण सोनिया गांधी पर भी आया था। लेकिन उन्होंने एक तरफ तो लोकसभा की

राजपाट

सदस्यता से इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ा था दूसरी तरफ मनमोहन सरकार ने कानून बदलकर एनएसी अध्यक्ष के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया था। झारखंड के 81 सदस्यीय सदन में फिलहाल झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और राजद का एक यानी यूपीए के कुल 49 सदस्य हैं। भाजपा की अपनी सदस्य संख्या 26 और सहयोगी आजसू के दो सदस्य हैं। यूपीए को डर है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे की दशा में भाजपा उनके विधायकों की खरीद-फरोख्त कर खुद सरकार बना सकती है। यह बात अलग है कि अभी तक महाराष्ट्र की तर्ज पर उसे झारखंड में कोई एकनाथ शिंदे नही मिल पाया है। हालांकि कांग्रेस में सेंध आसान दिख रही थी पर पार्टी अपने विधायकों को बुरी नजर से बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी तरह झामुमो में भी टूट का खतरा फिलहाल तो टल गया ही दिखता है। लेकिन हकीकत तो राज्यपाल के फैसले के बाद ही सामने आ पाएगी कि सियासी घटनाक्रम क्या मोड़ लेगा।

गले में फांस

केसीआर को पटना में पत्रकारों ने उलझा दिया। विपक्षी मोर्चे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस समय केंद्र की सरकार और भाजपा के सबसे प्रबल विरोधी हैं। वे 2024 की तैयारी को अभी से अंजाम देना चाहते हैं। ममता बनर्जी के बाद वही एक चेहरा हैं जो भाजपा को कड़ी चुनौती देने की बात कहते हैं। लेकिन तेलंगाना में भाजपा उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है। इसलिए केसीआर के सामने अपना अस्तित्व बचाने का भी संकट है। तभी तो पटना में एलान किया कि वे 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन पत्रकारों ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। सवाल दाग दिया कि क्या वे प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। केसीआर ने फरमाया कि इसका फैसला करने वाले वे कौन होते हैं। यह फैसला सब दल मिलकर करेंगे। दुविधा तो यही है कि विपक्षी एका हो पाए इससे पहले ही प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का सवाल गैर भाजपा विपक्ष के गले की फांस बन जाता है। कांग्रेस को अछूत मान भी लें तो भी बाकी सारे गैर भाजपाई विरोधी दल एकजुट हो कहां पा रहे हैं।

बात जिम्मेदारी की...

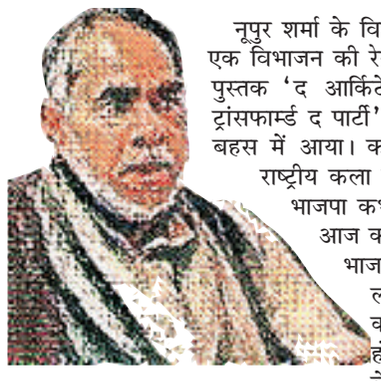

नूपुर शर्मा के विवाद ने भाजपा से जुड़े बुद्धिजीवियों के बीच एक विभाजन की रेखा खींच दी है। हाल ही में अजय सिंह की पुस्तक 'द आर्किटेक्ट आफ न्यू बीजेपी : हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफार्म्ड द पार्टी' के विमोचन समारोह में यह मुद्दा फिर बीच बहस में आया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष रामबहादुर राय ने कहा कि भाजपा कभी काडर आधारित पार्टी नहीं थी, यह न तो आज काडर आधारित है और न आगे होगी। उन्होंने भाजपा को जनमानस पर आधारित और लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में रखा। राय ने कहा कि अगर भाजपा काडर आधारित पार्टी होती तो नूपुर शर्मा का इस्तीफा नहीं होता या वे प्रवक्ता ही नहीं नियुक्त होतीं। राय ने यहां तक कहा कि अगर नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाला गया तो उनके बयान की जिम्मेदारी लेते हुए भाजपा अध्यक्ष का भी इस्तीफा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह व जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। हालांकि, राम बहादुर राय की इस टिप्पणी पर वहां मौजूद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मौन ही रखा।

(संकलन : मृणाल वल्लरी)

आप में कुछ काला है

यह सियासत का वह सच है जिसने सफेद होने के हर दावे को झूठ बना दिया है। सियासत किसी मुल्क के दायरे में बंधी नहीं होती न ही किसी सूबे की मिल्कियत। लिहाजा हिंदुस्तान की राजधानी के इलाकाई सूबे की सियासी सफेदी पर बहस चली तो हर परत काली निकली। अलग बात है कि सूबाई हुकूमत के उस पार खड़े सियासी खिलाड़ियों के गले में टंगी सफेदी मशीन वाले तमगे की चमक ज्यादा चटक हो गई है। बेशक दिल्ली की शराब नीति के पीछे कानूनी खामियां हों मगर मयखानों के इर्द-गिर्द उठे बवंडर में खामियों का गुबार कम नहीं। कीचड़ कुछ इस कदर उछाली गई कि हर चेहरा काला नजर आने लगा। सबसे अलग दिखने वाली सियासी जमात को राजपूती खून का वास्ता देना पड़े तो शक की सुई का थम जाना लाजिम है। 'आप' तो पहले से ही उन भगोड़ों में शुमार हैं जो हर फर्जी शिकायत पर माफीनामा लिए खड़े मिले। आने वाले महीनों की सियासी तपिश आज ही महसूस होने लगी है।

-एमके मिश्रा, रांची, झारखंड।

सत्ता बनाम भ्रष्टाचार

इतिहासकार लार्ड एक्टन ने उन्नीसवीं सदी में कहा था कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। इतिहास के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति वे बने जो सत्ता के शिखर पर रहे। इस हिसाब से राज्यों की छोटी सत्ता के मुकाबले केंद्र की बड़ी सत्ता के भ्रष्ट होने की संभावना ज्यादा है। प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआइ, आयकर विभाग आदि ने विपक्षी सरकारों का भ्रष्टाचार तो उजागर कर दिया। मगर क्या इनमें इतनी कूवत है कि वे देश की सबसे बड़ी सरकार के भ्रष्टाचार को भी उजागर कर सकें? सत्ताधारी राजग सरकार में कुछ लोग ईमानदार हो सकते हैं। मगर क्या उनके सभी विधायक और सांसद ईमानदार हैं जबकि उनमें से कई आपराधाकि रेकार्ड वाले हैं।

-बृजेश माथुर, बृज विहार, गाजियाबाद।

आपके पत्र

आम का जवाब बबूल

समस्त देशवासियों को मालूम है कि भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर किस बुनियाद पर आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप से दिल्ली सहित देश की जनता को जरूर निराशा हुई होगी। जांच के नतीजे तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन फौरी तौर पर जो बात सामने नजर आई, विशेषकर छीटाकशी के दरमियान, वह यह थी कि बात हो रही थी आम की जवाब दिए जा रहे थे बबूल के बारे में। आप क्या परोस रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि जनता वही सुनेगी तो यह गलतफहमी है। सही सवाल तो है कि अगर स्कूली व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो फिर अफसरों, मंत्रियों के कितने बच्चे वहां पढ़ते हैं? भ्रष्टाचार की जांच की आंच पड़ने मात्र से अस्मिता की पहचान की याद दिलाने की नौबत क्यों आई?

-मुकेश कुमार मनन, पटना।

कठघरे में क्रांति

कहां अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए थे और अब उन्हीं आरोपों के कठघरे में हैं। असंगत और बचकाना बातें करके जिस तरह केजरीवाल मनीष सिसोदिया का बचाव कर रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि वे भी कहीं न कहीं उसमें सम्मिलित हैं। अगर ऐसा न होता तो वे तत्काल सिसोदिया को मंत्रिमंडल से हटा देते। धारा-302 के तहत दर्ज मामलों में से बहुत से मामले साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं होते तो क्या 302 के तहत मुकदमे दर्ज होने बंद हो जाएं? हमें तो नहीं लगता कि केजरीवाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जगह अपनी आम आदमी पार्टी को प्रतिस्थापित कर पाएंगे, सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है।

-राधेश्याम मिश्र, लखनऊ।

एकतरफा कार्रवाई

इन दिनों विभिन्न जांच एजंसियों की कार्यशीलता बढ़ गई है। इसका परिणाम है कि बड़ी मात्रा में काला धन भी बाहर आ रहा है। यह कार्यशीलता मुख्य रूप से विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही दिख रही है। इसलिए इसका एक राजनीतिक संदेश भी जा रहा है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही जांच एजंसियों का अति सक्रिय हो जाना इसका ताजा उदाहरण है। वही नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) जैसी संवैधानिक संस्था की अकर्मण्यता भी हमारे सामने है। देश में कोयला खनन और टू-जी घोटाले हुए जो सीएजी की रपटों से उजागर हुए थे। अब उस तरह की किसी रिपोर्ट से कोई हंगामा नहीं होता है।

-दल सिंह खरत, गाजीपुर, दिल्ली।

कायाकल्प

आम आदमी पार्टी का यह कायाकल्प भारतीय राजनीति के लिए दुखद है। अब जनता विकल्प की किन बातों पर भरोसा करेगी। इधर कुआं तो उधर खाई में से एक को चुनना होगा। इससे अच्छा तो यह होता कि आम आदमी पार्टी न तो स्थापित होती और न सपना दिखता।

-अंकुर सिंह, गाजियाबाद।

विशेष पन्ना कैसा लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है :
vishesh.jansatta@expressindia.com

कई खूबियां बनाती हैं नौसेना के युद्धपोत विक्रांत को खास

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

दो फुटबाल मैदानों के आकार के बराबर एक फ्लाइट डेक, 18 मंजिल की ऊंचाई, एक दिन में 16,000 चपाती बना सकने वाले रसोई के उपकरण, समुद्र में हर पल नजर रखने वाली प्रणाली, 2,500 किलोमीटर लंबी केबल जैसी विशेषताएं भारत के स्वदेश निर्मित पहले विमानवाहक पोत 'आइएनएस' विक्रांत को खास बनाती हैं।

तैरता नगर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोच्चि में 'आइएनएस विक्रांत' का जलावतरण किया और इसे 'तैरता नगर' तथा 'तैरती हवाई पट्टी' करार दिया जो 5,000 घरों को रोशन करने समान विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम है। इस 45,000 टन वजनी युद्धपोत को आज जब भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तो इसके फ्लाइट डेक पर एक उन्नत हल्का हेलिकाप्टर (एएलएच), एक कामोव-31 और एक मिग-29के खड़ा था। यदि किसी को जहाज के मार्ग और लाबी से गुजरना हो तो उसे लगभग 12 किमी चलना पड़ेगा।

युद्धपोत के नियंत्रण कक्ष में नौसेना का अधिकारी।

क्षमता

2,500 किमी से अधिक की केबल
एक दिन में 16,000 चपातियां और 6,000 इडली बनाने में सक्षम स्वचालित प्रणाली।
सीटी स्कैन मशीन के साथ पूरी तरह कार्यात्मक अस्पताल, देश में युद्धपोत में पहला।
दो आपरेशन थिएटर, चालक दल के 1,600 सदस्य, 2,200 से अधिक कक्ष
18 मंजिल ऊंचाई।

उपकरण

आरएएन-40एल 3डी हवाई निगरानी रडार
एमएफ-स्टार (नौसेना रडार प्रणाली)
टीएसीएन (सामरिक हवाई नौवहन प्रणाली)
रेजिस्टर-ई एविएशन काम्प्लेक्स शक्ति ईडब्लू सूट (पोत विध्वंसक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा की एक इलेक्ट्रानिक परत)
डाइवर निगरानी प्रणाली
ईएलके-7036 वीयूएचएफ कोमिंट

लंबाई : 262.5 मीटर
चौड़ाई : 62.5 मीटर
विस्थापन : 42,800 टन
गति : 28 समुद्री मील
विद्युत उत्पादन क्षमता: 24 मेगावाट
7,500 समुद्री मील की क्रूजिंग रेंज
700 से अधिक सीढ़ियां

आइएनएस विक्रांत पूर्व सरकारों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

कांग्रेस ने शुक्रवार को भारत के पहले स्वदेश निर्मित पोत 'आइएनएस विक्रांत' को राष्ट्र को समर्पित करने का श्रेय लेने के लिए केंद्र सरकार के दावे पर सवाल उठाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के योगदान को उचित स्थान नहीं देकर पाखंड किया है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय नौसेना, उसके डिजाइन ब्यूरो और कोच्चि शिपयार्ड को बधाई दी और 'आइएनएस विक्रांत' को नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने को देश की समुद्री सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह ऐसी उपलब्धि है जिससे देश की मजबूती को बल मिलेगा। एक वीडियो साझा करते हुए रमेश ने यह भी कहा कि तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने 12 अगस्त 2013 को भारत के पहले स्वदेशनिर्मित विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रांत को 'लांच' किया था। प्रधानमंत्री ने इसे आज बेड़े में शामिल किया है। आत्मनिर्भर भारत 2014 से पहले भी था। इससे जुड़े पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान की भी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया जाना 1999 के बाद की सभी सरकारों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कृष्णा मेनन ने ब्रिटेन से इसे हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।

रमेश ने कहा कि आइएनएस विक्रांत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना भारतीय नौसेना के इंजीनियरों, अधिकारियों और कोच्चि शिपयार्ड के कर्मचारियों को समर्पित है।

देश में कोरोना संक्रमण के 6,168 मामले आए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

देश में एक दिन में कोरोना विषाणु संक्रमण के 6,168 मामले आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 4,44,42,507 हो गई। वहीं, संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 59,210 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.13 फीसद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 21 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 5,27,932 पर पहुंच गई है। इन 21 मौतों में वे दो लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनःमिलान करते हुए केरल ने संक्रमण से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में डाले हैं। चौबीस घंटे में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 3,538 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.68 फीसद हो गई है।

नीतीश कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर बताया

पटना, 2 सितंबर (भाषा)।

भाजपा के साथ पिछले महीने गठबंधन टूटने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 'राष्ट्रीय राजनीति' में आने की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर कहा कि वह प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं।जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के मुख्यालय पर पत्रकारों के केंद्र की राजनीति में भूमिका निभाने संबंधी सवालों के जवाब में नीतीश का जवाब था, 'छोड़िए ये सब बात।' वहीं, पार्टी के मुख्यालय पर लगे बड़े-बड़े पोस्टरों में से कुछ पर लिखा है 'प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा।' इन नारों से विभिन्न अर्थ निकाले जा सकते हैं।

वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने 'भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए ध्रुवीकरण' के तंज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने यह भी याद दिलाने का प्रयास किया कि वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के शासनकाल के दौरान केंद्र में थे। राज्य के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक से महज कुछ ही घंटे पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचे नीतीश ने कहा कि वह शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसके एक दिन बाद होने वाली राष्ट्रीय परिषद की तैयारियां देखने आए हैं।

पोस्टर कर रहे अलग कहानी बयां

पटना, 2 सितंबर (भाषा)।

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता नीतीश कुमार भले ही अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे हों, लेकिन यहां पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। इनमें से कुछ में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है, तो कुछ में उन्हें (कुमार को) एक ऐसा व्यक्ति बताया गया है, जो 2024 में बदलाव का सूत्रपात करेगा। एक पोस्टर में कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री ' जुमला नहीं, हकीकत' हैं , जबकि एक अन्य में 'मन की नहीं, काम की' बात कही गई है। इस तरह इन पोस्टर में कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरूद्ध पेश किया गया है।

प्रधानमंत्री देश की सेवा में जुटे हैं तो परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार बचाने में : नड्डा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि एक ओर देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए एक योद्धा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेवा में जुटे हुए हैं तो दूसरी ओर परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को, अपने बेटे-बेटी, भतीजे और दामाद को बचाने में जी-जान से लगी हुई हैं। नड्डा दो दिन के हरियाणा के दौर पर हैं और शुक्रवार को कैथल में अमृतकाल संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बदल रहा है और सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन वाली मनोहर लाल खट्टर सरकार हरियाणा के जन-जन के कल्याण के लिए कटिबद्ध भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न तो वैचारिक पार्टी है, न राष्ट्रीय और न ही प्रादेशिक।

भारत की बंदरगाह क्षमता आठ साल में दोगुनी हुई : प्रधानमंत्री

मंगलुरू (कर्नाटक), 2 सितंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास विकसित भारत के निर्माण का मार्ग है और यही लोगों की आकांक्षा है।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी राज्य कर्नाटक में लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को तेजी से पूरा करने के लिए भाजपा सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, 'आज का भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दे रहा है क्योंकि यही विकसित भारत के निर्माण का मार्ग है। आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण सुविधा बढ़ाने के साथ ही बड़े पैमाने पर नए रोजगार का भी निर्माण करता है।

ट्विटर ने जानबूझ कर देश के कानून की अवज्ञा की : केंद्र

बंगलुरु, 2 सितंबर (एजंसी)।

केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि ट्विटर ने 'जानबूझकर' भारत के कानूनों का पालन नहीं किया और उसकी अवज्ञा की तथा देश की सुरक्षा में इस सोशल मीडिया मंच की कोई भूमिका नहीं है।

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआइटीवाई) ने गुरुवार को ट्वीट हटाने और अकाउंट ब्लाक करने से जुड़े सरकारी आदेशों के खिलाफ ट्विटर की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियों के संबंध में पेश 101 पन्नों के बयान में यह दलील दी। राजनीतिक ट्वीट हटाने के निर्देश से संबंधित ट्विटर के दावों पर केंद्र ने कहा कि उसने सिर्फ असत्यापित खातों को ब्लाक करने के लिए कहा था। याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए सरकार ने कहा, 'याचिकाकर्ता ने जानबूझकर कानूनों का अनुपालन नहीं किया और उनकी अवज्ञा की। प्रतिवादी नंबर-2 (केंद्र) की अनुवर्ती कार्रवाई और 27 जून 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद ही याचिकाकर्ता ने अचानक सभी दिशा-निर्देशों पर अमल शुरू कर दिया, जिसकी वजह वही बेहतर जानता है।'

ट्विटर ने 39 यूआरएल (यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर) को ब्लाक करने के संबंध में दायर आदेश को चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। ट्विटर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ट्वीट हटाने और अकाउंट ब्लाक करने से संबंधित सरकारी नोटिस से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

कंपनी ने कहा कि उसके सोशल मीडिया मंच पर सामग्री साझा करने वाले लोगों को संबंधित सामग्री हटाने के लिए कहने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। हालांकि, सरकार ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि चूंकि ट्विटर एक मध्यस्थ है, इसलिए उपयोगकर्ताओं को सूचित करना माइक्रो-ब्लागिंग वेबसाइट की जिम्मेदारी थी।

केंद्र ने कहा, 'जब सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा कोई मुद्दा उठता है तो कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है, न कि किसी मंच पर। लिहाजा, कौन-सी सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों के लिए सही है या नहीं, इसे तय करने की अनुमति मंच को नहीं दी जानी चाहिए।' सरकार ने दलील दी कि आनलाइन मंच द्वारा बनाई गई कोई भी निजी नीति या नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अधीन आते हैं।

भारत व आस्ट्रेलिया प्रारंभिक शिक्षा, कौशल विकास में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भारत और आस्ट्रेलिया प्रारंभिक शिक्षा व कौशल विकास के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमत हो गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि हमने ज्ञान के क्षेत्र में अपने मजबूत एवं विविधतापूर्व सहयोग एवं दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गति प्रदान करने पर सहमति जताई है। दूसरी ओर, प्रधान ने इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्री नदीम अनवर मकारिम के साथ भी बैठक की और समग्र सामरिक सहयोग की पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच अकादमिक एवं कौशल विकास भागीदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। प्रधान इन दिनों इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी20 समूह के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं।

प्रधान ने शुक्रवार को आस्ट्रेलिया की प्रारंभिक शिक्षा मंत्री एनी एली व यूनेस्को की सहायक महानिदेशक स्टेफानिया गियानिनी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने व प्रारंभिक एवं स्कूली शिक्षा में आपसी संपर्कों को गहरा बनाने पर चर्चा की। प्रधान ने आस्ट्रेलिया की प्रारंभिक शिक्षा मंत्री एनी एली के साथ बैठक के बाद कहा कि एली से आरंभिक शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को गहरा बनाने के बारे में सार्थक चर्चा हुई।

प्रधान ने कहा कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच उच्च शिक्षा, शोध और कौशल विकास के क्षेत्र में विविधतापूर्ण सहयोग है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में संपर्कों को गहरा बनाने से दोनों देशों के बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए मजबूत आधार बनाया जा सकेगा। प्रधान ने यूनेस्को की सहायक महानिदेशक स्टेफानिया गियानिनी के साथ भी बैठक की और 2030 के शिक्षा एजंडे पर चर्चा की।

थरूर ने निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की

पेज 1 का बाकी

रही है और पार्टी के भीतर इस पर बहस तेज हो गई है। सूत्रों ने बताया कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे थरूर ने मिस्त्री को पत्र लिखा और निर्वाचन सूची प्रकाशित करने की मांग की। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में 10 प्रस्तावक शामिल हैं जो प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) के प्रतिनिधि (डेलिगेट) होंगे। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इन प्रतिनिधियों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उनका नाम अंतिम सूची में नहीं आता तो नामांकन पत्र खारिज हो सकता है। नेताओं द्वारा लिखे गए पत्रों और निर्वाचन सूची के प्रकाशन की मांग को लेकर उठ रही आवाजों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस ने इसे तवज्जो नहीं दी और कहा कि एक के बाद एक आवाजें उठ रही हैं कि राहुल गांधी को पार्टी का अगला अध्यक्ष होना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, 'अगर आप देश के कोने-कोने के हर कार्यकर्ता से चाय पीते या खाना खाते समय पूछेंगे, तो वह यही कहेगा, हमारी इच्छा है कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालें।' उन्होंने कहा, 'कांग्रेस का चुनावी कार्यक्रम सबके सामने है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस के संविधान और पूरी व्यवस्था के अनुसार होगा।'मनीष तिवारी, कार्ति चिदंबरम और थरूर ने बुधवार को भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की थी। कांग्रेस के 'जी 23' समूह में शामिल रहे तिवारी के साथ ही थरूर ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े निर्वाचक मंडल की सूची सार्वजनिक नहीं किए जाने पर वस्तुतः सवाल खड़े करते हुए बुधवार को कहा था कि चुनाव से संबंधित पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का इरादा जता चुके थरूर ने तिवारी से सहमति जताई और कहा कि हर किसी को यह जानने का हक है कि कौन नामित कर सकता है तथा कौन मतदान कर सकता है।

रेलवे बोर्ड ने विभिन्न भत्तों की समीक्षा के लिए कहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

परिचालन खर्च बढ़ने से चिंतित रेलवे बोर्ड ने सातों जोन से 'अतिरिक्त समय अवधि', रात्रिकालीन कार्य और यात्रा तथा ईंधन एवं रखरखाव के लिए मिलने वाले भत्तों की समीक्षा करने को कहा है।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके त्रिपाठी ने तिमाही समीक्षा बैठक में पाया कि परिचालन से जुड़े खर्चे काफी अधिक हैं। चालू वित्त वर्ष में मई तक सातों जोन में यह रेलवे के पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 26 प्रतिशत औसत वृद्धि से कहीं ऊपर है। ये जोन हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (37.9 प्रतिशत), उत्तर रेलवे (35.3 प्रतिशत), दक्षिण-मध्य रेलवे (34.8 प्रतिशत), दक्षिण-पश्चिम रेलवे (33.1 प्रतिशत), उत्तर-पश्चिम रेलवे (29 प्रतिशत), पश्चिम रेलवे (28 प्रतिशत) और उत्तर-मध्य रेलवे (27.3 प्रतिशत)। एक सवाल के जवाब में रेलवे ने कहा कि परिचालन खर्च को लेकर 2022-23 के लिए कुल बजटीय अनुमान 2.32 लाख करोड़ रुपए है। चूंकि खातों का आडिट होना बाकी है, संबंधित आंकड़े अस्थायी हैं। विभाग ने कहा कि रेलवे ने वित्त मंत्रालय के व्यय नियंत्रण और प्रबंधन पर दिए गए दिशानिर्देश को जारी किया है। विभिन्न मोर्चों पर मितव्ययिता और किफायती उपायों को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, ईंधन की खपत को अनुकूलतम बनाने के साथ माल भंडार प्रबंधन में सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान रेलवे बोर्ड ने जोन को अपने खर्च को कम करने के लिए 'तत्काल कदम' उठाने का निर्देश दिया और महाप्रबंधकों को इस संदर्भ में कार्ययोजना बनाने को कहा।

सीने से उतर गया गुलामी का बोझ

पेज 1 का बाकी

था कि नया 'निशान' समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप होगा। विक्रांत के नौसेना के बेड़े में शामिल होने के साथ ही भारत अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है, जिसमें स्वदेशी रूप से एक विमानवाहक पोत का निर्माण करने की विशिष्ट क्षमता है। कुल 262 मीटर लंबा तथा 62 मीटर चौड़ा यह जहाज 28 समुद्री मील से लेकर 7500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है। बीस हजार करोड़ रुपए की लागत से बना यह विमान वाहक जहाज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह देश में बने 'एडवांस्ड लाइट हेलिकाप्टर' (एएलएच) के अलावा मिग-29के लड़ाकू विमान सहित 30 विमान संचालित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा, 'यदि लक्ष्य दुरंत हैं, यात्राएं दिगंत हैं, समंदर और चुनौतियां अनंत हैं तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत।'महिला शक्ति पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ' विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा, तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेंगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति, ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है।'नौसेना का बजट बढ़ाने पर मोदी ने कहा, 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया है, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता हैं। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं।'

छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को ट्रेन से फेंका, मौत

पेज 1 का बाकी

ने कहा, 'प्रारंभिक जांच के दौरान यह पता चला है कि घटना में एक आरोपी शामिल था। हम उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।'उन्होंने कहा कि जब ट्रेन टोहाना पहुंची, तो बिलख रहे बच्चे ने अपने पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि महिला का शव बाद में टोहाना से कुछ दूरी पर पटरियों के पास मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भारतीय नौसेना को मिला नया ध्वज

पेज 1 का बाकी

परिचालन क्षमता का प्रतीक है।भारतीय नौसेना का मूल औपनिवेशिक काल में जाता है, और एक स्वतंत्र भारत के नौसैन्य बल के रूप में अपनी पहचान धारण से पहले इसके नामकरण में पिछली कुछ शताब्दियों में कई बदलाव हुए हैं।नेवल डाकयार्ड मुंबई (एनडीएम) में विरासत दीर्घा में एक पैनल पर प्रदर्शित जानकारी के अनुसार, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में सूरत में अपनी गतिविधियों की शुरुआत की और उसके जहाजों को माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी के मरीन के रूप में जाना जाता है। इसने कैंटन में सेंट जार्ज क्रास के साथ धारीदार ध्वज अपनाया।

सूरत से बंबई में गतिविधियों के स्थानांतरण के साथ, बांबे मरीन का गठन 1686 में किया गया था।वर्ष 1707 में, ब्रिटिश संघ के ध्वज से कैंटन में सेंट जार्ज क्रॉस को बदल दिया, और 1801 में ब्रिटिश ध्वज को विकर्ण के साथ लाल धारियों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। साल 1830 में, बांबे मरीन का नाम बदलकर 'हर मेजेस्टीज इंडियन नेवी' कर दिया गया।नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 1863 से 1877 तक इसका नाम 'बांबे मरीन' रहा और इसके बाद इसका नाम 'हर मेजेस्टीज इंडियन मरीन' कर दिया गया। 1892 में नाम 'रायल इंडियन मरीन' कर दिया गया। 1934 में 'रायल इंडियन मरीन' को 'रायल इंडियन नेवी' नाम दिया गया और इसकी सेवाओं को मान्यता देते हुए इसे 1935 में 'किंग्स कलर' प्रस्तुत किया गया था।वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के साथ, स्वतंत्रता के बाद, रायल इंडियन नेवी को रायल इंडियन नेवी और रायल पाकिस्तान नेवी में विभाजित कर दिया गया। 26 जनवरी, 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ, उपसर्ग रायल को हटा दिया गया और इसे भारतीय नौसेना (इंडियन नेवी) के रूप में नया नाम दिया गया।छब्बीस जनवरी 1950 से 2001 तक, भारतीय नौसेना ने ब्रिटिश नौसैन्य ध्वज के एक संशोधित संस्करण का उपयोग किया, और कैंटन में यूनियन जैक को भारतीय तिरंगे से बदल दिया गया।

15 अगस्त, 2001 से, इस ध्वज को भारतीय नौसेना के क्रेस्ट वाले एक सफेद ध्वज के साथ बदल दिया गया, क्योंकि पिछला ध्वज भारत के औपनिवेशिक अतीत को प्रतिबिंबित करता था और यह 2004 तक बना रहा।वर्ष 2004 के बाद से, क्रास के केंद्र में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को जोड़ने के साथ ही ध्वज को सेंट जार्ज क्रास डिजाइन में वापस बदल दिया गया और 2014 में प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य - सत्यमेव जयते - को नीचे जोड़ा गया।

तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत

पेज 1 का बाकी

ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की तीस्ता के खिलाफ दी गई तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए यह कदम उठाया। पीठ ने उन्हें हाईकोर्ट द्वारा मामले पर विचार किए जाने तक अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है।न्यायाधीशों ने कहा-तीस्ता एक महिला हैं। वह दो महीनों से हिरासत में हैं और जांच तंत्र को सात दिनों की अवधि के लिए हिरासत में पूछताछ का लाभ भी मिला है। तीस्ता के खिलाफ कथित अपराध 2002 से संबंधित हैं और अधिक से अधिक 2012 तक संबंधित दस्तावेज पेश करने की मांग की गई थी।

पीठ ने कहा-हमारे विचार में अपीलकर्ता अंतरिम जमानत पर रिहा होने की हकदार है। यह कहा जाना चाहिए कि जैसा कि सालिसिटर जनरल ने तर्क दिया था कि मामला अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए या नहीं। उस पर हाईकोर्ट द्वारा विचार किया जाना है। हम केवल इस दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं कि क्या मामले पर विचार के दौरान अपीलकर्ता की हिरासत पर जोर दिया जाना चाहिए।तुषार मेहता ने तीस्ता को अंतरिम जमानत न देने और मामले को गुजरात हाईकोर्ट के विचार के लिए छोड़ देने पर लगातार जोर दिया तो अदालत का सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा प्राथमिकी में और कुछ नहीं है। दोनों दिखाते हैं कि यह सच नहीं है। मजिस्ट्रेट के सामने गवाह के बयान रखने पर गुजरात सरकार पर भी पीठ ने सवाल उठाया और कहा कि ये बयान सीलकवर में होते हैं। ये मजिस्ट्रेट के पास होने चाहिए। आपको ये बयान कैसे मिले। ये मजिस्ट्रेट कोर्ट की कस्टडी में होने चाहिए। ये कोर्ट से कोर्ट आने चाहिए।तीस्ता सीतलवाड की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 124 लोगों को उम्रकैद हुई है। ये कैसे कह सकते हैं कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ। ये सब एक उद्देश्य के लिए है। ये चाहते हैं कि तीस्ता ताउम्र जेल से बाहर न आए। 20 साल से सरकार क्या करती रही। ये हलफनामे 2002-2003 के हैं, तो ये जालसाजी कैसे हो गए? ये हलफनामे इस मामले में दाखिल नहीं किए गए। ये पहले के मामलों में दाखिल किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को जमानत देते हुए कहा कि तीस्ता को जल्द से जल्द संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय कर जमानत दे। तीस्ता जांच में सहयोग करेंगी।

बाढ़ का पानी घटा, संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा

लखनऊ, 2 सितंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बलिया समेत कई जिलों में अब बाढ़ का पानी कम होने लगा है और संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि राहत और बचाव के लिए पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है।

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में अब गंगा और वरुणा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है और दोनों नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का पानी अब कम होने लगा है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद संबंधित क्षेत्रों से पानी कम होना शुरू हो गया है। वरुणा पार के भी कई रिहायशी इलाकों से पानी निकल गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है, परंतु इसके साथ ही बाढ़ के पानी के साथ आए गाद और गंदगी की सफाई और उससे फैलने वाली संक्रामक बीमारियों से लोगों में भय व्याप्त है। वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डा. संदीप चौधरी ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जगह-जगह कीचड़ और जल जमाव से संक्रामक रोग न फैले इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। सीएमओ ने बताया कि संक्रामक रोगों से बचाव के लिए कार्रवाई तेज कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि जल जमाव वाले स्थानों पर मच्छरजनित बीमारी डेंगू, मलेरिया आदि के फैलने की आशंका अधिक होती है लिहाजा बाढ़ से प्रभावित रहे सभी क्षेत्रों में एंटी लार्वा का छिड़काव करने के साथ ही नगर निगम के सहयोग से फागिंग भी कराई जा रही है।

जिला मलेरिया अधिकारी एस सी पाण्डेय ने बताया कि एंटी लार्वा के छिड़काव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ड्रा से 15 कर्मियों को मांगा है, जो विभिन्न इलाकों में एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहे हैं।

प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार बलिया जिले में गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट के बाद जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों का प्रसार रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर दिया है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
ENGINEERS INDIA LIMITED (A Govt. of India Undertaking)

पंजीकृत कार्यालय : इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, भारत
Regd.Office: Engineers India Bhawan, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066, India
ई-मेल / e-mail: company.secretary@eil.co.in, दूरभाष / Phone: 011-26762855/2580
कंपनी सचिवालय / COMPANY SECRETARIAT

57वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना ई-वोटिंग / रिकार्ड तिथि की जानकारी

कम्पनी की 57वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) **मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को अप. 03.00 बजे (आईएसटी)**, एजीएम आयोजन की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020, सर्कुलर नंबर 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, सर्कुलर नंबर 19/2021 दिनांकित 08 दिसम्बर, 2021, सर्कुलर नंबर 21/2021 दिनांकित 14 दिसम्बर, 2021 तथा सर्कुलर नंबर 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022 और सेबी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 (सामूहिक रूप से "**संबद्ध सर्कुलर्स**" कहे गए हैं) के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर कम्पनी के सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से, आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

संबद्ध सर्कुलर्स एवं सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु पृथक्कृत और समेकित वित्तीय विवरण, निदेशकगण की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ 01 सितम्बर, 2022 को कम्पनी के उन सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(स) के पास पंजीकृत है अथवा जो एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के प्रयोजनार्थ अपनी ई-मेल आईडी हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट (आरटीए), अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड https://mailupd.alankit.com के पास अस्थायी रूप से पंजीकृत करवा चुके हैं। सूचनाओं की भौतिक प्रतियां वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित डाक द्वारा उन शेयरधारकों को भेजी जा रही हैं, जिनके द्वारा अनुरोध किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य अपना अनुरोध कम्पनी/आरटीए को **company.secretary@eil.co.in** अथवा **rta@alankit.com** पर भेज सकते हैं। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट **www.engineersindia.com** पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** क्रमानुसार पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु एजेन्सी) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध होंगे। एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज निरीक्षण के लिए कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु अनुदेश :

कम्पनी इसके सदस्यों को एजीएम में पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों पर उनके वोट डालने के अधिकार के प्रयोग हेतु इलेक्ट्रॉनिक साधनों ("**ई-वोटिंग**") द्वारा वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यगण यहां नीचे वर्णित तिथियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("**रिमोट ई-वोटिंग**") का प्रयोग करते हुए अपना वोट रिमोटली डाल सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिन सदस्यों ने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकेंगे।

कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एजेन्सी के तौर पर एनएसडीएल की सेवाएं अनुबंधित की हैं।

ई-वोटिंग के संबंध में जानकारी और अनुदेश सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लॉगइन क्रेडेंशियल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। भौतिक रूप, अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की विधि एजीएम की सूचना में दी गई है।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी :

रिमोट ई-वोटिंग का आरंभनः	**शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को पूर्वा. 9.00 बजे (आईएसटी)**
रिमोट ई-वोटिंग का समापनः	**सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी)**

उपरोक्त तिथि और समय के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल उपरोक्त अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

कोई व्यक्ति, जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 को दर्ज मौजूद है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने अथवा एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का हकदार होगा।

ई-मेल पता पंजीकरण/अद्यतनीकरण की विधि निम्नानुसार है :

- भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत/अद्यतन नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे हमारे कम्पनी के आरटीए मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, कार्यालय पता : 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 से सम्पर्क करें अथवा **rta@alankit.com** पर ई-मेल भेजें।
- अभौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पंजीकृत/अद्यतन नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पास पंजीकृत/अद्यतन करवा लें, जिनके पास उनका डीमैट खाता है।
- कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी का सदस्य बनता है अथवा कोई सदस्य जिसने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाई है और कट-ऑफ तिथि को शेयरों का धारक है, वह भी एजीएम की सूचना, जोकि कम्पनी की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है, में दिए गए अनुदेशों के अनुरूप पंजीकृत करवा सकता है और एनएसडीएल को **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर लॉगइन क्रेडेंशियल्स प्राप्त कर सकता है। ये सदस्य एजीएम की सूचना में कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट विधि में ई-वोटिंग अनुदेशों का प्रयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके सदस्य भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु एजीएम में पुनः वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

सदस्यगण यह भी नोट करें कि कम्पनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश (₹ 1/- प्रति इक्विटी शेयर), यदि सदस्यों की 57वीं एजीएम में उनके द्वारा अनुमोदित किया गया, की अधिकारिता के अभिनिश्चयन के प्रयोजन हेतु **सोमवार, 5 सितम्बर, 2022** की तिथि रिकार्ड तिथि निर्धारित की गई है।

यदि आपको एजीएम में भाग लेने एवं ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई संदेह अथवा समस्या है, तो आप **www.evoting.nsdl.com** में डाउनलोड सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यूज") तथा ई-वोटिंग मैनुअल देखें अथवा सुश्री सोनी सिंह को **evoting@nsdl.co.in** पर ई-मेल भेजें। सदस्यगण टोल फ्री नंबर 18001020 990 अथवा 1800224430 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। किसी अन्य पूछताछ के लिए, आप हमसे भी नीचे दिए विवरण के अनुसार सम्पर्क कर सकते हैं :

कम्पनी सेक्रेटरी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, फोन : 011-2610 0258. ई-मेल : company.secretary@eil.co.in

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
एस. के. पाढ़ी
कम्पनी सेक्रेटरी

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 02.09.2022

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement or the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated August 26, 2022 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

7NR RETAIL LIMITED

Our Company was originally incorporated on December 21, 2012, as "7NR Retail Private Limited" as a Private Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. Thereafter, our Company was converted into a Public Limited Company and accordingly the name of our Company was changed to "7NR Retail Limited" pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at the EGM held on March 11, 2017. A fresh certificate of incorporation consequent upon conversion to Public Limited Company was issued on March 22, 2017 by Registrar of Companies, Ahmedabad, Gujarat.

Corporate Identification Number: L52320GJ2012PLC073076 | **Registered Office:** Godown No-1, 234/1+234/2, FP-69/3, Sadashiv Kanto, B/h Bajaj Process, Narol Chokdi, Narol, Ahmedabad – 382 405
Telephone: + 91-97271-23838; Email id: info@7nrretailltd.in | **Website:** www.7nrretailltd.in; | **Contact Person:** Ms. Prachi Chobisa, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. NIKUNJ AGRAWAL AND MR. UMANG TRIVEDI

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR MARKET RENUNCIATION*	ISSUE CLOSES ON**
6th September, 2022	15th September, 2022	20th September, 2022

Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.

***Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time, provided that this Issue will not remain open in excess of 15 (Fifteen) days from the Issue Opening Date. Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.*

ISSUE OF 11,66,95,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RE. 1/- EACH ("EQUITY SHARES") OF 7NR RETAIL LIMITED ("7NR" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 1.40/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 0.40/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO RS. 16,33,73,000/- ON RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) EQUITY SHARE FOR EVERY 1 (ONE) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. 23RD AUGUST, 2022(THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS 1.40 TIMES OF FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 145 OF THIS FINAL LETTER OF OFFER.

ASBA	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!! *Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details read section on ASBA below.

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, bearing reference number SEBI/HO/CFD/CIR/CFD/DIL/67/2020 dated April 21, 2020, SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 dated May 6, 2020, and SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/136 dated July 24, 2020 (Collectively hereafter referred to as "SEBI Rights Issue Circulars") and SEBI circular SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 dated December 30, 2009, SEBI circular CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and the SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 (Collectively hereafter referred to as "ASBA Circulars"), all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use either the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, see "Making of an Application through the ASBA Process" on page 148 of the Letter of Offer.

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working days prior to the Issue Closing Date i.e Friday, September 16, 2022, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date i.e Monday, September 19, 2022.

Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have opened their demat accounts after the Record Date, shall adhere to procedure for participating in this Issue mentioned on page 151 of the Letter of Offer.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company namely 7NR Retail Limited– Rights Issue Suspense Escrow Demat Account (Account Number –IN301330 41172945)

In accordance with the SEBI Rights Issue Circulars, the Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have not furnished the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working days prior to the Issue Closing Date, i.e. Friday, September 16, 2022, shall not be eligible to make an Application for Rights Equity Shares against their Rights Entitlements with respect to the equity shares held in physical form.

PROCEDURE FOR APPLICATION: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars, all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use either the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details of procedure for application by the Resident Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on the Record Date i.e. August 23, 2022, see "Procedure for Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form" on page 151 of the Letter of Offer.

PROCEDURE FOR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS: A shareholder, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with an SCSB, prior to making the Application. Shareholders desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online / electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Shareholders should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorization to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application.

APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM: Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working days prior to the Issue Closing Date i.e Friday, September 16, 2022, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date i.e Monday, September 19, 2022. They may also communicate with the Registrar with the help of the helpline number (+91-44-40020710/0706/0741) and their email address (priya@cameoindia.com)

ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM: PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES APPLIED FOR IN THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH OUR EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE I.E. AUGUST 23, 2022.

DISPATCH OF THE ABRIDGED LETTER OF OFFER ("ALOF") AND APPLICATION FORM: The Dispatch of the ALOF and Application Form for the Issue was completed on September 01, 2022 by the Registrar to the Issue.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account (namely, 7NR Retail Limited Rights Issue Suspense Escrow Demat Account) opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in the account of the IEPF authority; or (b) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or the Equity Shares which are lying in the unclaimed suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (c) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (d) credit of the Rights Entitlements returned / reversed / failed; or (e) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings, if any; or (f) non-institutional equity shareholders in the United States.

APPLICATIONS ON PLAIN PAPER UNDER ASBA PROCESS: An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through e-mail or physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar, Stock Exchanges. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB.

Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address or is a U.S. Person or in the United States.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not been titled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his / her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

a) Name of our Company, being 7NR Retail Limited;
b) Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
c) Folio Number (in case of Eligible Equity Share holders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) / DP and Client ID;
d) Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to this Issue
e) Number of Equity Shares held as on Record Date;
f) Allotment option – only dematerialized form;
g) Number of Equity Shares entitled to;
h) Number of Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;
i) Number of additional Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for);
j) Total number of Equity Shares applied for;
k) Total amount paid at the rate of Rs. 1.40/- per Equity Share;
l) Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB;
m) In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;
n) Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
o) Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and
p) All such Eligible Equity Shareholders are deemed to have accepted the following:

"I/ We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation except under circumstances that will result in compliance with any applicable laws or regulations. We satisfy, and each account for which we are acting satisfies, all suitability standards for Shareholders in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of our residence.

I/ We understand and agree that the Rights Entitlement and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulations, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act.

I/ We (i) am/ are, and the person, if any, for whose account I/ we am/ are acquiring such Rights Entitlement and/ or the Rights Equity Shares is/ are, outside the U.S., (ii) am/ are not a "U.S. Person" as defined in ("Regulations"), and (iii) is/ are acquiring the Rights Entitlement and/ or the Rights Equity Shares in an offshore transaction meeting the requirements of Regulations.

I/ We acknowledge that the Company, our affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements."

In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, as applicable, including cases where a Shareholders submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Shareholders are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Shareholders. The plain paper Application form at will be available on the website of the Registrar at https://rights.cameoindia.com/7nrretail

Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in the Shareholders' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

LAST DATE FOR APPLICATION:

The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is 20th September, 2022, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 15 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB on or before the Issue Closing Date or such date as maybe extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in "Basis of Allotment" mentioned below.

Please note that on the Issue Closing Date, (i) Applications through ASBA process will be uploaded until 5:00 P.M. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.

Please ensure that the Application Form and necessary details are filled in. In place of Application number, Shareholders can mention the reference number of the e-mail received from Registrar informing about their Rights Entitlement or last eight digits of the demat account. Alternatively, SCSBs may mention their internal reference number in place of application number.

PROCEDURE FOR RENUNCIATION OF RIGHTS ENTITLEMENTS:

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchanges **(the "On Market Renunciation")**; or (b) through an off-market transfer **(the" Off Market Renunciation"),** during the Renunciation Period. The Shareholders should have the demat Rights Entitlements credited / lying in his / her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism.

Shareholders may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. Shareholders who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock-broker regarding any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Shareholders on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

Our Company accept no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Shareholders.

On Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading / selling them on the secondary market platform of the Stock Exchanges through a registered stock-broker in the same manner as the existing Equity Shares of our Company.

In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchanges under ISIN INE413X20019 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Opening Date, our Company will obtain the approval from the Stock Exchanges for trading of Rights Entitlements. No assurance can be given regarding the active or sustained On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchanges from time to time.

The Rights Entitlements are tradable in dematerialized form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is one Rights Entitlements.

The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., from 6th September, 2022 to 15th September, 2022 (both days inclusive).

The Shareholders holding the Rights Entitlements who desire to sell their Rights Entitlements will have to do so through their registered stock-brokers by quoting the ISIN INE413X20019 and indicating the details of the Rights Entitlements they intend to trade.

The Shareholders can place order for sale of Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The On Market Renunciation shall take place electronically on secondary market platform of BSE under automatic order matching mechanism and on 'T+2 rolling settlement basis', where 'T' refers to the date of trading. The transactions will be settled on trade-for-trade basis. Upon execution of the order, the stock- broker will issue a contract note in accordance with the requirements of the Stock Exchange and the SEBI.

Off Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by way of an off-market transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only.

Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date to enable Renouncees to subscribe to the Equity Shares in the Issue.

The Shareholders holding the Rights Entitlements who desire to transfer their Rights Entitlements will have to do so through their depository participant by issuing a delivery instruction slip quoting the ISIN INE413X20019, the details of the buyer and the details of the Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt instruction slip to their depository participant. The Shareholders can transfer Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The instructions for transfer of Rights Entitlements can be issued during the working hours of the depository participants.

The detailed rules for transfer of Rights Entitlements through off-market transfer shall be as specified by the NSDL and CDSL from time to time.

INVESTORS TO KINDLY NOTE THAT AFTER PURCHASING THE RIGHTS ENTITLEMENTS THROUGH ON MARKETRENUNCIATION / OFF MARKET RENUNCIATION, AN APPLICATION HAS TO BE MADE FOR SUBSCRIBING THE RIGHTSEQUITY SHARES. IF NO APPLICATION IS MADE BY THE PURCHASER OF RIGHTS ENTITLEMENTSON OR BEFORE ISSUECLOSING DATE THEN SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS WILL GET LAPSED AND SHALL BE EXTINGUISHED AFTER THEISSUE CLOSING DATE. NO RIGHTS EQUITY SHARES FOR SUCH LAPSED RIGHTS ENTITLEMENTS WILL BE CREDITED,EVEN IF SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS WERE PURCHASED FROM MARKET AND THE PURCHASER WILL LOOSE THEAMOUNTPAID TO ACQUIRE SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS.

FOR PROCEDUREOF APPLICATION BY SHAREHOLDERS WHO HAVE PURCHASED THE RIGHT ENTITLEMENT THROUGH ON MARKET RENUNCIATION / OFF MARKET RENUNCIATION, PLEASE REFER TO THE HEADING TITLED "PROCEDUREFOR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS" ON PAGE 148 OF THE LETTER OF OFFER.

Listing and trading of the Equity Shares to be issued pursuant to this Issue

Subject to receipt of the listing and trading approvals, the Equity Shares proposed to be issued on a rights basis shall be listed and admitted for trading on the Stock Exchange. Unless otherwise permitted by the SEBI ICDR Regulations, the Equity Shares allotted pursuant to this Issue will be listed as soon as practicable and all steps for completion of necessary formalities for listing and commencement of trading in the Equity Shares will be taken within such period prescribed under the SEBI ICDR Regulations. Our Company has received in-principle approval from the BSE through letter bearing reference number DCS/RIGHT/VJ/FIP/2292/2022-23 dated 7th June, 2022. Our Company will apply to the Stock Exchange for final approvals for the listing and trading of the Equity Shares subsequent to their Allotment. No assurance can be given regarding the active or sustained trading in the Equity Shares or the price at which the Equity Shares offered under this Issue will trade after the listing thereof.

The existing Equity Shares are listed and traded on BSE (Scrip Code: 540615) under the ISIN: INE413X01027. The Equity Shares shall be credited to a temporary ISIN which will be frozen until the receipt of the final listing / trading approvals from the Stock Exchange. Upon receipt of such listing and trading approvals, the Equity Shares shall be debited from such temporary ISIN and credited to the new ISIN for the Equity Shares and thereafter be available for trading and the temporary ISIN shall be permanently deactivated in the depository system of CDSL and NSDL.

The listing and trading of the Equity Shares issued pursuant to this Issue shall be based on the current regulatory framework then applicable. Accordingly, any change in the regulatory regime would affect the listing and trading schedule.

In case our Company fails to obtain listing or trading permission from the Stock Exchange, our Company shall refund through verifiable means / unblock the respective ASBA Accounts, the entire monies received / blocked within four days of receipt to intimation from the Stock Exchanges, rejecting the application for listing of the Equity Shares, and if any such money is not refunded / unblocked within four days after our Company becomes liable to repay it, our Company and every director of our Company who is an officer-in-default shall, on and from the expiry of the fourth day, be jointly and severally liable to repay that money with interest at rates prescribed under applicable law.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI

The Final Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is below Rs. 5000 Lakhs.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE):

As required, a copy of this Final Letter of Offer has been submitted to the BSE Limited. The Disclaimer Clause as intimated by BSE Limited to us, post scrutiny of this Final Letter of Offer is set out below:

"BSE Limited ("the Exchange") has given, vide its letter dated 7th June, 2022 permission to this Company to use the Exchange's name in this Letter of Offer as the stock exchanges on which this Company's securities are proposed to be listed. The Exchange has scrutinized this Letter of Offer for its limited internal purpose of deciding on the matter of granting the aforesaid permission to this Company. The Exchange does not in any manner:

- Warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of this Letter of Offer; or
- Warrant that this Company's securities will be listed or will continue to be listed on the Exchange; or
- Take any responsibility for the financial or other soundness of this Company, its promoters, its management or any scheme or project of this Company;

and it should not for any reason be deemed or construed that this Letter of Offer has been cleared or approved by the Exchange. Every person who desires to apply for or otherwise acquires any securities of this Company may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Exchange whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such subscription/acquisition whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or for any other reason whatsoever.

Neither the delivery of this Final Letter of Offer nor any sale hereunder, shall under any circumstances create any implication that there has been no change in our Company's affairs from the date hereof or the date of such information or that the information contained herein is correct as of any time subsequent to this date or the date of such information. Each person who exercises Rights Entitlements and subscribes for Equity Shares, or who purchases Rights Entitlements or Equity Shares shall do so in accordance with the restrictions set out below.

DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS:

In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Relaxation Circulars, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent / dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

Further, this Final Letter of Offer will be sent / dispatched to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address and who have made a request in this regard. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Letter of Offer will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Final Letter of Offer will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

Shareholders can access this Final Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Equity Shares under applicable laws) on the websites of:

(i) Our Company at https://www.7nrretailltd.in/;
(ii) The Registrar at https://rights.cameoindia.com/7nrretail;
(iii) The Stock Exchanges at www.bseindia.com

Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., https://rights.cameoindia.com/7nrretail) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (for Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company (i.e., https://www.7nrretailltd.in/).

BANKERTO THE ISSUE AND REFUND BANK: INDUSIND BANK LIMITED

MONITORING AGENCY:Not Applicable

FOR RISK FACTORS AND OTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE LETTER OF OFFER AND ALOF.

OTHER IMPORTANTLINKS AND HELPLINE:

The Investors canvisit following links for the below-mentioned purposes:

Frequently asked questions and online / electronic dedicated Shareholders helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Shareholders: https://rights.cameoindia.com/7nrretail

Updation of / e-mail address / phone or mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: https://rights.cameoindia.com/7nrretail

Updation of Indian address by way of sending an email to priya@cameoindia.com

Updation of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: https://rights.cameoindia.com/7nrretail

Submission of self-attested PAN, client mastersheet and demat account details by non-resident Eligible Equity Shareholders: investor@cameoindia.com

REGISTRAR TO THE ISSUE	BANKER TO AN ISSUE
CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED Subramanian Building, 1 Club House Road, Chennai - 600 002 | **Tel :** +91 - 44 4002 0700 **Email:** priya@cameoindia.com | **Investor Grievance Email id:** investor@cameoindia.com **Website:** https://rights.cameoindia.com/7nrretail | **Contact Person:** Ms. K. Sreepriya **SEBI Registration No:** INR000003753 | **CIN:** U67120TN1998PLC041613	**INDUSIND BANK LIMITED** 2, Zodiac Square, opp. Gurudwara, S.G. Highway, Bodakdev, Ahmedabad 380054, India **Tel :** +91-8605397938 | **Email:** Karan.malik@indusind.com | **Website:** www.indusind.com **Contact Person:** Mr. Karan Patel | **CIN:** L65191PN1994PLC076333

Date: 2nd September, 2022
Place: Ahmedabad

For, 7NR Retail Limited
SD/-
Prachi Chobisa
Company Secretary

Disclaimer: *Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with Stock Exchange i.e. BSE Limited. The Letter of Offer is available on the website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and the website of the RTA i.e. Cameo Corporate Services Limited at https://rights.cameoindia.com/7nrretail. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 23 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.*

खबर कोना

चेक गणराज्य के प्राग में यूरोबास्केट ग्रुप डी बास्केटबाल मैच के दौरान फिनलैंड के खिलाफ इजराइल के जेक कोहेन चुनौती देते हुए।

जडेजा चोट के कारण एशिया कप से बाहर, अक्षर लेंगे जगह

दुबई, 2 सितंबर (भाषा)।

भारतीय हरफनमौला रविंद्र जडेजा घुटने की चोट के कारण शुक्रवार को एशिया कप के बचे हुए मैचों से बाहर हो गए और टीम में उनकी जगह अक्षर पटेल लेंगे। जडेजा ने भारत की टूर्नामेंट के शुरूआती मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीसीसीआइ ने एक बयान में कहा, 'अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने मौजूदा एशिया कप में रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल को चुना है।' इसके अनुसार, 'रविंद्र जडेजा को दाएं पैर के घुटने में चोट लगी है और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वह इस समय बीसीसीआइ की चिकित्सा टीम की देखरेख में हैं।' बयान में कहा गया, 'अक्षर पटेल को टीम में 'स्टैंडबाय' खिलाड़ियों में चुना गया था, वह जल्द ही दुबई में टीम से जुड़ेंगे।'

मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रीमियर लीग में लगातार तीसरी जीत

लीस्टर, 2 सितंबर (एपी)।

मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लीस्टर सिटी को 1-0 से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबाल प्रतियोगिता में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। यूनाइटेड के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से मैच के आखिरी क्षणों में ही मैदान पर उतरे। जादौन सांचो के 23वें मिनट में किए गए गोल से यूनाइटेड ने बढ़त बनाई और आखिर तक उसे बरकरार रखा। यूनाइटेड ने इससे पहले लिवरपूल और साउथम्पटन को हराया था। रोनाल्डो ने 68वें मिनट में मैदान पर कदम रखा और उन्होंने इसके बाद अपनी जीवंत छाप छोड़ी। उनका बाईसिकिल किक से लगाया गया एक शाट मामूली अंतर से गोल में जाने से रह गया था। कर अपने करियर का दूसरा डब्ल्यूटीए खिताब जीता।

राष्ट्रमंडल खेल में नहीं खेल पाना निराशाजनक : नवजोत

बंगलुरु, 2 सितंबर (भाषा)।

भारतीय महिला हाकी टीम की मिडफील्डर नवजोत कौर ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेल जैसी बड़ी खेल प्रतियोगिता में नहीं खेल पाना निराशाजनक था। वह कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण इस प्रतियोगिता में नहीं खेल पाई थी। यह 27 वर्षीय खिलाड़ी बर्मिंघम पहुंचने पर कोविड-19 से संक्रमित पाई गई थी और उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा था। भारत की तरफ से 200 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी नवजोत ने यहां राष्ट्रीय शिविर से इतर कहा, ' इस तरह से टीम को छोड़ना बेहद निराशाजनक था। इसे स्वीकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था।' उन्होंने कहा, 'मैं इससे पहले कभी किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने से नहीं चूकी थी इसलिए पहली बार अपने करिअर में इस तरह की परिस्थिति से पार पाना मेरे लिए आसान नहीं था।'

कल्याण ने भूटिया को हराया, पहले खिलाड़ी जो बने अध्यक्ष

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) को अपने 85 साल के इतिहास में शुक्रवार को पहली बार कल्याण चौबे के रूप में पहला ऐसा अध्यक्ष मिला जो पूर्व में खिलाड़ी रह चुके हैं। चौबे ने अध्यक्ष पद के चुनाव में पूर्व दिग्गज फुटबालर बाइचुंग भूटिया को हराया।

सिक्किम के रहने वाले 45 वर्षीय भूटिया का नामांकन पत्र भरते समय उनके राज्य संघ का प्रतिनिधि भी प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बना था। पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर सीट से हारने वाले भाजपा के राजनीतिज्ञ चौबे कभी भारतीय सीनियर टीम से नहीं खेले हालांकि वह कुछ अवसरों पर टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने हालांकि आयु वर्ग के टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के लिए गोलकीपर के रूप में खेले हैं। भूटिया और चौबे एक समय ईस्ट बंगाल में साथी खिलाड़ी थे।

कर्नाटक फुटबाल संघ के अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक एनए हारिस ने उपाध्यक्ष के एकमात्र पद पर जीत दर्ज की। उन्होंने राजस्थान फुटबाल संघ के मानवेंद्र सिंह को 29-5 से हराया। अरुणाचल प्रदेश के किपा अजय ने आंध्र प्रदेश के गोपालकृष्णा कोसाराजू को 32-1 से हराकर कोषाध्यक्ष पद हासिल किया। कोसाराजू ने अध्यक्ष पद के लिए भूटिया के नाम का प्रस्ताव रखा था जबकि मानवेंद्र ने उसका समर्थन किया था। कार्यकारिणी के 14 सदस्यों के लिए इतने ही उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था और उन्हें निर्विरोध चुना गया।

एआइएफएफ के चुनाव के साथ ही भारतीय फुटबाल में पिछले कुछ महीनों में चले नाटकीय घटनाक्रम का भी पटाक्षेप हो गया। इस दौरान भारतीय फुटबाल ने दिसंबर 2020 में चुनाव न कराने के कारण पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को बर्खास्त होते हुए देखा। इसके बाद प्रशासकों की समिति गठित की गई जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय ने बर्खास्त कर दिया था। विश्व फुटबाल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने 'तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव' का हवाला देकर इस बीच भारत को निलंबित भी कर दिया था।

नई कार्यकारी समिति में जीपी पालगुना, अविजीत पाल, पी अनिलकुमार, वलंका नताशा अलेमाओ, मालोजी राजे छत्रपति, मेनला एथेनपा, मोहन लाल, आरिफ अली, के नीबौ सेखोज, लालनघिंग्लोवा हमर, दीपक शर्मा, विजय बाली और सैयद इम्तियाज हुसैन शामिल हैं।

अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ)

मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर 45 वर्षीय चौबे ने 33-1 से जीत दर्ज की। उनकी जीत पहले ही तय लग रही थी क्योंकि पूर्व कप्तान भूटिया को राज्य संघों के प्रतिनिधियों के 34 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में बहुत अधिक समर्थन हासिल नहीं था।

भूटिया ने चुनाव के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, ' मैं भारतीय फुटबाल की बेहतरी के लिए भविष्य में भी काम करता रहूंगा। कल्याण को बधाई। मुझे उम्मीद है कि वह भारतीय फुटबाल को आगे लेकर जाएंगे।' उन्होंने कहा,'भारतीय फुटबाल प्रशंसकों का आभार जिन्होंने मेरा समर्थन किया। मैं चुनाव से पहले भी भारतीय फुटबाल के लिए काम कर रहा था और आगे भी इसे जारी रखूंगा। हां मैं कार्यकारी समिति का सदस्य हूं।'

मुकाबला

स्पेन के राफेल नडाल यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दौर के दौरान इटली के फैबियो फोगनिनी को शाट रिटर्न करते हुए।

'केंद्रीय मंत्री ने चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया'

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

राजस्थान फुटबाल संघ प्रमुख और कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) के चुनावों के नतीजे को 'प्रभावित' किया। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में महान भारतीय फुटबालर बाईचुंग भूटिया को पश्चिम बंगाल से भाजपा नेता और ईस्ट बंगाल के पूर्व साथी कल्याण चौबे से 1-33 से करारी हार झेलनी पड़ी।

राजस्थान के पूर्व सांसद सिंह ने पत्रकारों से कहा, 'चुनाव प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप जारी रहा और बीती रात केंद्रीय मंत्री (रिजीजू) ने संघ के सदस्यों पर दबाव बनाया कि उन्हें बाईचुंग के लिए वोट नहीं करना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह हस्तक्षेप अस्वीकार्य है और भारतीय फुटबाल के लिए नुकसानदायक है। फुटबाल तो पहले ही परेशानी में घिरी है और अब यह परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी।'

एआइएफएफ

कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह ने दावा किया कि केंद्रीय कानून मंत्री रिजीजू ने चुनाव की पूर्व संध्या पर राज्य संघ सदस्यों के होटल जाकर उन्हें भूटिया के खिलाफ वोट देने का दबाव बनाया।

जापान ओपन : कड़ी चुनौती पेश करने के बाद क्वार्टर फाइनल में हारे प्रणय

ओसाका, 2 सितंबर (भाषा)।

एचएस प्रणय को शुक्रवार को यहां विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता चीनी ताइपे के चाउ तिएन चेन से तीन गेम तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इससे जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती भी समाप्त हो गई। इस 30 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने आखिर तक हार नहीं मानी लेकिन चाउ ने भी किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती और एक घंटा 20 मिनट तक चले इस मैच में 21-17, 15-21, 22-20 से जीत दर्ज की। बाकी खिलाड़ियों के जल्दी बाहर होने के बाद भारत की उम्मीदें प्रणय पर ही टिकी थी।

पिछले कुछ समय से निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे प्रणय ने पहला गेम गंवाने के बाद अच्छी वापसी की और तीसरे व निर्णायक गेम में भी आखिरी क्षणों तक खुद को मुकाबले में बनाए रखा। इस मैच से पहले पिछले दो मैचों में चाउ पर जीत दर्ज करने वाले प्रणय ने पहले गेम में शुरू से दबदबा बना दिया था और एक समय वह 12-8 से बढ़त पर थे। चाउ ने हालांकि प्रणय की गलतियों का फायदा उठाया और जल्द ही 15-14 से आगे हो गए।

सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट

निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे प्रणय ने पहला गेम गंवाने के बाद अच्छी वापसी की और तीसरे व निर्णायक गेम में भी आखिरी क्षणों तक खुद को मुकाबले में

बनाए रखा। इस मैच से पहले पिछले दो मैचों में चाउ पर जीत दर्ज करने वाले प्रणय ने पहले गेम में शुरू से दबाव बना दिया था।

राफेल नडाल ने की शानदार वापसी, स्वियातेक भी जीतीं

न्यूयार्क, 2 सितंबर (एपी)।

राफेल नडाल पहला सेट गंवाने और गलती से अपनी नाक को चोट पहुंचाने के बावजूद यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बनाने में सफल रहे जबकि महिलाओं में दो बार की फ्रेंच ओपन चैंपियन इगा स्वियातेक ने आसान जीत दर्ज की। बाईस बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल ने फैबियो फोगनिनी पर 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 से जीत दर्ज की। इस बीच चौथे सेट में गलती से वह अपने ही रैकेट से नाक पर चोट लगा बैठे जिससे उनकी नाक से खून बहने लग गया था।

स्वियातेक ने 2017 की यूएस ओपन विजेता स्लोएन स्टीफंस को दूसरे दौर में 6-3, 6-2 से हराकर इस सत्र में अपनी डब्लूटीए टूर की 50वीं जीत दर्ज की। महिला वर्ग में पिछले साल से फाइनल में पहुंचने वाली चार खिलाड़ियों में से अब केवल छठी वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका ही टूर्नामेंट में बनी हुई हैं। उन्होंने दूसरे सेट में 5< ु> —< ु> 1 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके काया कानेपी को 2-6, 7-6 (8), 6-4 से हराया।

लेकिन चौथी वरीयता प्राप्त पाउला बडोसा को क्रोएशियाई पेट्रा मार्टिच से 6-7 (5), 6-1, 6-2 से हार का सामना करना पड़ा।

महिला वर्ग में गुरुवार को जिन अन्य खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की उनमें जेसिका पेगुला, गार्बिने मुगुरुजा, बेलिंडा बेनसिच और विक्टोरिया अजारेंका शामिल हैं।

यूएस ओपन टेनिस

विजय विश्व चैंपियनशिप के लिए भारत की 48 सदस्यीय टीम में

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

ओलंपिक रजत पदक विजेता विजय कुमार को आगामी आइएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में चुना गया। वह लंदन ओलंपिक खेलों में पोडियम स्थान हासिल करने के बाद अपने पहले बड़े टूर्नामेंट में खेलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआइ) ने मिस्र के काहिरा में 12 से 25 अक्तूबर तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए 48 सदस्यीय भारतीय राइफल और पिस्टल टीम की घोषणा की।

लंदन ओलंपिक में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल रजत पदक विजेता पिस्टल निशानेबाज ने इस साल राष्ट्रीय टीम में वापसी की थी। उन्होंने कंधे की गंभीर चोट के कारण ब्रेक लिया था। शिमला में हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में तैनात पुलिस उपाधीक्षक विजय ने पांच साल के अंतराल बाद प्रतिस्पर्धी निशानेबाजी में वापसी की थी। पांच बार के राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता विजय 2017 में सेना छोड़कर हिमाचल प्रदेश पुलिस से जुड़ गए थे। क्रोएशिया के ओसिजेक में 19 सितंबर से शुरू हो रही शाटगन विश्व चैंपियनशिप के लिए 24 सदस्यीय टीम पहले ही घोषित हो चुकी है।

मौजूदा टीम में कई निशानेबाज पहली बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे जिसमें विजय और अंजुम मोदगिल (विश्व चैंपियनशिप की पूर्व पदक विजेता) अनुभव लेकर आएंगे।

निशानेबाजी

बीसीसीआइ ने पिछले साल ई-नीलामी में खरीदा था नीरज चोपड़ा का भाला

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मृति चिन्हों के संग्रह की जब ई नीलामी हुई थी तब ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का भाला बीसीसीआइ ने डेढ करोड़ रुपए में खरीदा था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी । चोपड़ा ने तोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर उनसे मुलाकात में उन्हें अपना भाला उपहार में दिया था। इस भाले समेत कई चीजों की ई नीलामी की गई जिनसे मिली रकम 'नमामि गंगे कार्यक्रम ' को गई । यह नीलामी सितंबर-अक्तूबर 2021 में हुई थी।

बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा, 'बीसीसीआइ ने नीरज के भाले पर बोली लगाई थी। इसके अलावा भी कुछ और वस्तुओं पर बोली लगाई । नमामि गंगे एक नेक काम है और बोर्ड के पदाधिकारियों को लगा कि देश के प्रमुख खेल संगठनों में से एक होने के नाते यह देश के प्रति हमारा कर्तव्य है ।' बीसीसीआइ ने कोरोना महामारी के दौरान भी 'पीएम केयर्स फंड' में 51 करोड़ रूपए दिए थे।

बोर्ड ने चोपड़ा के भाले के अलावा भारतीय पैरालम्पिक दल के हस्ताक्षर वाला अंगवस्त्र भी एक करोड़ रुपए में खरीदा था। चोपड़ा का भाला ई नीलामी में सबसे महंगा बिका जबकि भवानी देवी की तलवार सवा करोड़ रूपए में और पैरालम्पिक चैंपियन सुमित अंतिल का भाला एक करोड़ 20 हजार रुपए में बिका। लवलीना बोरगोहेन के मुक्केबाजी दस्ताने 91 लाख रूपए में बिके । ई नीलामी में 1348 स्मृति चिन्ह बिके जिनमें खेलों से जुड़े सामान भी थे।

विलियम्स बहनों की जोड़ी हारी | **टेनिस** | **दर्शकों ने खड़े होकर किया अभिवादन**

महिला युगल के पहले दौर में हारीं सेरेना और वीनस

न्यूयार्क, 2 सितंबर (एपी)।

सेरेना और वीनस विलियम्स साढे चार साल बाद जब कोर्ट पर एक साथ उतरी तो उन्होंने हर पल का भरपूर लुत्फ उठाया लेकिन विश्व टेनिस की मशहूर विलियम्स बहनों की जोड़ी को यूएस ओपन के महिला युगल के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा।

विलियम्स बहनों को फ्लशिंग मीडोज में लूसी हेराडेका और लिंडा नोस्कोवा की चेक गणराज्य की जोड़ी ने 7-6 (5), 6-4 से हराया। वीनस और सेरेना जब कोर्ट से बाहर निकल रही थी तो दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उनकी प्रतिद्वंदी भी उनका सामना करके अभिभूत थी।

ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पदार्पण कर रही 17 वर्षीय नोस्कोवा ने कहा, 'जब मुझे पता चला कि हमें उन दोनों का सामना करना है तो मैं अवाक रह गई। मेरे कहने का मतलब है कि वे दोनों दिग्गज है और मैं हमेशा उनकी विशेषकर सेरेना की प्रशंसक रही हूं। वह शुरू से मेरी आदर्श रही हैं।' उनकी साथी हेराडेका ने कहा, 'मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने उन पर जीत दर्ज की है। मुझे अफसोस है कि हमने उन्हें हराया है लेकिन मैं बहुत खुश भी हूं कि हमने ऐसा किया।' आर्थर ऐस स्टेडियम में इससे पहले महिला या पुरुष वर्ग में पहले दौर के युगल मैच कभी नहीं खेले गए थे लेकिन एक ही परिवार की इन दो सदस्यों के लिए यूएस ओपन के आयोजकों ने अपने नियम भी बदल दिए और दर्शकों ने भी इस मैच का भरपूर आनंद लिया। वीनस और सेरेना ने मिलकर युगल में 14 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं।

विलियम्स बहनों ने मैच के बाद इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने इससे पहले आखिरी बार फ्रेंच ओपन 2018 में जोड़ी बनाई थी। यह चौथा अवसर है जबकि किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के महिला युगल में उन्हें पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2013 में फ्रेंच ओपन में वे पहले दौर में बाहर हो गई थी।

टेनिस

विलियम्स बहनों ने इससे पहले आखिरी बार फ्रेंच ओपन 2018 में जोड़ी बनाई थी। यह चौथा अवसर है जबकि किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के महिला युगल में उन्हें पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा।

रजिस्ट्रेशन नं. एमएम एंड पीओ/ डब्ल्यूबी/ आरएनपी- 351/2003, आरएनआई नं. 53037/1991, वर्ष 31, अंक 302 हवाई शुल्क : अगरतला 4 रु., सिलचर और पोर्टब्लेयर 6 रु.।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए वी श्रीनिवासन द्वारा सरस्वती प्रिंट फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड, 789 चौभागा (पश्चिम), कोलकाता-700105 से मुद्रित व वी श्रीनिवासन द्वारा जेएल नं. 29 व 30, नेशनल हाइवे- 6, मौजा- प्रशस्था व अंकुरहाटी, पोस्ट- सलप, डोमजूर, हावड़ा- 711409 से
प्रकाशित। फोन : (033) 66043800 फैक्स : (033) 66043825 व 66043847 **बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक : मुकेश भारद्वाज*** *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट : दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।